(iv) Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred-forty third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests.

Status of Implementation of Recommendations Contained in the Eighty-eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): Sir, I beg to lay a copy of the statement on the status of implementation of recommendations contained in the Eighty-eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

Status of Implementation of Recommendations Contained in the One Hundred-forty Fourth and One Hundred-forty Fifth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science And Technology, Environment And Forests

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I beg to lay a copy each of the statemens on the:

(i) Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred-forty fourth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests; and

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the One Hundred-forty fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests.

GOVERNMENT BILLS—Contd.

The Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

''कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।''

महोदय, जनगणना 2001 के अनुसार 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले बच्चों की संख्या 15.78 करोड़ है। भारत में, आमतौर पर यह समझा जाता है कि बच्चे ईश्वर की देन हैं, जिनका परिवार और समाज, दोनों द्वारा अच्छे तरीके से प्यार और स्नेह से पालन-पोषण किया जाना चाहिए, लेकिन अनेक कारकों जैसे गरीबी, सामाजिक कुप्रथाओं और परंपरागत सामाजिक मूल्यों की अवहेलना के कारण बच्चों की उपेक्षा और शोषण के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए इन सभी कारकों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्येक बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, ताकि वह एक खुशहाल, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। हम प्रत्येक बच्चे को निर्धनता, निरक्षरता और शोषण के भंवर से मुक्त कराने का भी संकल्प लेते हैं। हमें अपने विशेष प्रयास बालिका के जीवन एवं अवसरों में सुधार लाने के लिए केंद्रित करने चाहिए।

बच्चे किसी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और उस देश का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनके चहुंमुखी विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बच्चों के समुचित विकास हेतु उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी वचनबद्ध है। इसलिए एक ओर तो बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना और दूसरी ओर उनके विकास एवं समृद्धि के लिए उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना एक स्वस्थ तथा सृजनात्मक समाज के निर्माण के लिए जरूरी है।

भारत के संविधान के अनेक ऐसे उपबंध हैं और कई ऐसे कानून हैं, जो बच्चों के विकास एवं संरक्षण से संबंधित हैं। बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों वाली एक राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त, 1974 को अंगीकार की गई थी। इस नीति में कहा गया है कि राज्य बच्चों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हेतु उनके जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात् तथा उनके वृद्धि काल के दौरान उन्हें पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा। नीति में इस प्रकार की सेवाओं का ब्यौरा भी दिया गया है। 1974 से अब तक बच्चों के विकास के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अनेक उपाय किए गए हैं। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु संसाधन मुहैया कराये हैं।

भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये। बाल अधिकार कन्वेंशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अनुसार हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह

जरूरी है कि वे कन्वेंशन में उल्लिखित बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं। मई, 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र में ''बच्चों हेतु उपयुक्त विश्व'' नामक एक निष्कर्ष दस्तावेज पारित किया गया, जिसमें वर्तमान दशक में सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यनीतियों और कार्यकलापों का उल्लेख किया गया। इसके फलस्वरूप, सरकार ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 तैयार की, जिसमें वर्तमान दशक के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को नये सिरे से निर्धारित किया गया। बच्चों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वर्ष 2003 में एक राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकार किया गया है।

हालांकि, पिछले वर्षों में बच्चों के संबंध में चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों और उन पर किए गए निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन ये सभी उपाय हमारे सम्मुख मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण से संबंधित विकास संसूचक भी अपेक्षित स्तर की प्रगति नहीं दर्शाते। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों से जुड़े सभी मुद्दों पर समग्र तरीके से दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के बारे में व्याप्त कतिपय नकारात्मक सामाजिक प्रथाएं और दृष्टिकोण भी सामने आये हैं। सामाजिक जांच से यह भी पता चला है कि बालिकाओं के साथ किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या और अवैध व्यापार इसके कुछ उदाहरण हैं। पूरे विश्व में संचार माध्यमों की सुगमता और प्रचार माध्यमों की लगातार बढ़ती पकड़ के कारण बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध अधिक संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं। बच्चों के शोषण के नए तरीके भी सामने आये हैं जैसे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अश्लील बाल साहित्य में बच्चों को इस्तेमाल करना। आपराधिक गिरोहों के बढ़ते जाल और संचार के सुगम एवं त्वरित माध्यमों तथा निर्धनता के कारण बच्चों का अवैध देह व्यापार बढ़ गया है। परिवार में लड़कियों के साथ भेदभाव के कारण उन्हें, शिक्षा समुचित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन सभी मामलों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

बच्चों के संबंध में बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से केन्द्र और राज्यों के बहुत से विभाग जुड़े हैं। आमतौर पर, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी भी होती है। बच्चों के समुचित विकास के लिए अपेक्षित सेवाओं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में अंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए, पूरे देश में बच्चों से संबंधित सभी क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इस विषय में सरकार को सुझाव देने के लिए एक कारगर तंत्र बनाना आवश्यक समझा जाता है। बच्चे समाज का सर्वाधिक कमजोर वर्ग है, क्योंकि वे अपनी जरूरतों और समस्याओं को एकजुट होकर व्यक्त नहीं कर पाते। चूंकि, देश के लगभग 40 करोड़ बच्चे अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए एक ऐसा सांविधिक निकाय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसकी सिफारिशों की अनदेखी न की जा सके और जो बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कारगर उपाय कर सके। तद्नुसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रस्ताव है कि बालक

अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 के अनुसार संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाये। विधेयक में राज्यों में राज्य आयोगों तथा बालक न्यायालयों का गठन करने का भी प्रस्ताव है।

यह विधेयक राज्य सरकारों तथा बच्चों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् तैयार किया गया है। विधेयक की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देने से पूर्व जनमत भी प्राप्त किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी परामर्श किया गया है।

2 मई, 2005 को इस विधेयक को लोक सभा में पेश किये जाने के पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया गया था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2005 में प्रस्तुत की गयी। समिति की संस्तुतियों पर मंत्रालय द्वारा गहन विचार किया गया और उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जो बच्चों के हित में थीं। विधेयक में संशोधनों को अंतिम रूप देने से पूर्व कतिपय कानूनी मुद्दों पर विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया गया।

चूंकि यह विधेयक बच्चों के हित में राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें, जिससे कि आयोग का यथाशीघ्र गठन किया जा सके।

The question was proposed

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला (राजस्थान): डिप्टी चैयरमेन साहब, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी जब संविधान संशोधन हम लोगों ने पास किया तो हाउस पूरा भरा हुआ था और वह भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखिले के लिए बच्चों के बारे में ही था चाहे वे स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों। उस वक्त यहां हाउस मे कोरम बहुत ज्यादा था। शायद 177 लोगों ने वोट किया, मगर जब हम यहां बच्चों के बारे में एक विधेयक लेकर आए हैं, You have brought a legislation for the children, I hardly can count people in the House. That itself shows the seriousness of the people, as far as children and their problems are concerned.

इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे यह बात यहां पर रखनी है कि इस विंटर सेशन के फेग एंड में जब कि सब अपने घर जाकर आराम से बैठे हैं, उस वक्त यह विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब सुरेश पचौरी जी यहां मौजूद हैं। मुझे मालूम है सुरेश पचौरी जी के मन में बच्चों के लिए बहुत हमदर्दी है। He is very much concerned about children. But, Mr. Minister, you could have brought this Bill at a time, in the beginning of the Session, when we would have shown our concerned for the children, for the future generation. Investment in children is our commitment to the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के जितने भी रिजोल्यूशंस हुए हैं,

कांफरेंसेस हुई हैं, कनवेंशेस हैं - उस को भारत ने शुरू से सपोर्ट किया, उन को ratified भी किया और अपने यहां कोशिश की कि उन का इम्प्लीमेंटेशन हो। मुझे याद है जब यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल सेशन चिल्ड्रन पर सितम्बर, 2001 में होने वाला था, उस से पहले इसी पार्लियामेंट के रूम नंबर 62 में मैंने आई॰ पी॰ यू॰ के प्रेसीडेंट होने के नाते यूनाइटेड नेशंस की चिल्ड्रन ऑर्गनाइजेशन ''यूनिसेफ'' के साथ मिलकर एक ''यस फॉर चिल्ड्रन कैम्पेन'' शुरू की थी। मैं यहां यह भी बताना चाहती हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी से हमने रिक्वैस्ट की थी कि वह ''यस फॉर चिल्ड्रन कैम्पेन'' की शुरूआत करें। उस में 10 क्रिटीकल एरियाज थे और उन में से एक क्रिटीकल एरिया था, जहां बच्चों की हैल्थ, एजुकेशन, एच॰ आई॰ वी॰ एड्स पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर शेल्टर और फूड सेक्युरिटी की बात थी। वहां एक क्रिटीकल एरिया यह भी था कि बच्चों की बात सुनें। मुझे अफसोस है कि आज इस सदन में बच्चों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहां इतने कम लोग हैं जो बच्चों के बारे में वे अपनी बात कह नहीं सकते। शायद उस की वजह यह कि हमारे बच्चे अभी वोटर नहीं हुए हैं क्योंकि वे हम लोगों को वोट दे नहीं सकते, अपनी राय भी नहीं दे सकते। इसलिए उनके बारे में कोई बात सुनने वाला नहीं हैं उन की कोई लॉबी नहीं है, उन के पीछे कोई सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है। क्योंकि बच्चे invisible चीज दिखायी देते हैं, इसलिए इतने कम लोग यहां हैं। मुझे कोई एतराज नहीं हैं कि कम लोग हों, मगर मुझे एतराज इस बात पर है कि अगर उस समय यह बिल लाते जब लोग यहां होते, सुनते और उस के बारे में अपनी राय देते। तब एक यूनिफार्म कमिटमेंट होता बच्चों के बारे में और मैं समझती हूं कि वह अच्छी बात होती।

वह ''यस फॉर चिल्ड्रन कैम्पेन'' जो हमने शुरू की थी, उस को हमने Burkina Faso WEGA II कांफरेंस में ले जाकर, 2 हजार डेलीगेट्स जो पूरी दुनिया के 140 डेमोक्रेसीज से आए थे, उन के सामने प्रजेंट किया। उस कैम्पेन को जब हमने आगे बढ़ाया तो मुझे यह बात यहां सदन में कहने में खुशी हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल सेशन में 2002 में गए तो 98 मिलियंस सिग्नेचर्स हम ने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किए जोकि 140 डेमोक्रेटिक कंट्रीज से आए थे। मुझे इस बात पर भी खुशी है कि हमारे पार्लियामेंट के डेलीगेशन में न सिर्फ बुर्किनाफासो के अंदर जो स्पेशल आई.पी.यू. के सेशन में डिस्कशन हुए थे, उस में चिल्ड्रन के बारे में बराबर भाग लिया। उस के साथ एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल कांफरेंस जो पहले सितम्बर 2001 में होने वाली थी, मगर जब 9/11 का वाकया हुआ और अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उस की वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइजेशन और दुनिया हिल गयी तो यू.एन. में वह सेशन 2002 में करने का निर्णय लिया गया। उस सेशन में जो मेन इश्यू था उस का टाइटल ''वर्ल्ड सिट फॉर चिल्ड्रन'' था। उस में भारत का प्रतिनिधित्व यहां के उस समय के एच॰ आर॰ डी॰ मिनिस्टर ने किया। हमने भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की तरफ से, डेमोक्रेसीज के एम.पीज. की तरफ से कुछ कमिटमेंट किए कि हम इस दुनिया को बच्चों के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी ओपिनियन को रिएटरेट किया।

श्री जयराम रमेश (आन्ध्र प्रदेश) : यह बिल चिल्ड्रन के बारे में है।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला : अगर मैं कहूं कि आप शायद इस हाउस में नए हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की एक सब से बड़ी जरूरत होती हैं ...(व्यवधान)... Let the Minister respond ...*(Interruptions)*... I don't understand what your problem is....*(Interruptions)*... Don't worry. I can handle him. मैंने इस हाउस को 17 साल हैंडल किया है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं हैंडल करना जानती हूं। मुझे मालूम है कि आपने दुनिया में इकॉनोमी पर बहुत काम किए होंगे ।

श्री उपसभापति : नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला : लेकिन इस हाउस में आप को थोड़े ही दिन हुए हैं, शायद साल भर हुआ होगा ..(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, नारायणसामी ..(व्यवधान)...

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला : लेकिन आप की जो इनटॉलरेंस है, डेमोक्रेटिक इनटॉलरेंस को आप थोड़ा सहन करें और दूसरे की बात सुनने की आप में तसल्ली हो तो मैं समझती हूं कि ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप को लगता है कि मैं यहां बकवास कर रही हूं तो आप बाहर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। मुझे लगता है डिस्टर्ब करने के लिए आप को डिप्टी चैयरमेन इजाजत नहीं देंगे। शायद आप को यह नहीं मालूम होगा कि मैंने यहां से, और वहां से 17 वर्ष यह चीज देखी है कि इस हाउस में किस तरह से भाषण होते हैं और किस तरह से टोका-टोकी होती है। मगर आप जो टोका-टोकी की एक नई प्रथा डाल रहे हैं। शायद मैंने ऐसा हाउस में कभी देखा नहीं था। बिल पर डिस्कसन शुरू नहीं हुआ, अगर मुझ से कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे बाहर डिस्कस कर सकते थे, मगर आप बच्चों की समस्याओं के ऊपर अगर आपत्ति लगाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता दल के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, यह बात आप के बारे में रजिस्टर होगी कि आप को बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं यहां यह कहना चाहती हूं कि मंत्री जी आप जो बिल लायी हैं, इस बिल के अंदर ... (व्यवधान) ...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, right from the beginning, she is making charges. Earlier, she was sitting there. She knows the dignity of the House. ...*(Interruptions)*... Right from the beginning, she is doing like this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Poojaryji, I request you not to interrrupt the Member ...*(Interruptions)*...

DR. (SHRIMATI) NAJMA. HEPTULLA: I understand the dignity of the House, hon. Member ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please carry on. ...*(Interruptions)*...Let the discussion go on. ...*(Interruptions)*...

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: डिग्निटी यह है कि अगर कोई बोल रहा हो तो उसे बोलने दिया जाए। मंत्री जी, मैं आप से कहना चाहती हूं कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि आप जो कमीशन बनाने की बात लेकर आई हैं, इस कमीशन का क्या मतलब है? इसलिए कि इस कमीशन में न तो टीथ हैं, न कोई इनके डायरेक्शन हैं, न इनकी रिकमंडेशन का सरकार के ऊपर कोई असर है, कोई कमिटमेंट है या सरकार के ऊपर यह मेनडेटरी है कि यह कमीशन अपनी राय देगा या अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मैं बिल के क्लॉज के ऊपर बाद में बोलूंगी। मुझे यह पूछना है कि क्या इस बिल के जरिए आप बच्चों को एजुकेशन का प्रोटेक्शन दे सकेंगी? क्या आप इस कमीशन के जरिए बच्चों की जो गरीबी है उस को दूर कर सकेंगी? क्या इस कमीशन के जरिए जो बच्चे आज गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं जिन के एडमिशन के लिए हम ने आज यहां बिल पास किया है क्या आप उस का प्रोटेक्शन कर सकेंगी? इस बारे में मैं आप को सिर्फ एक बात बताऊंगी। यह कल के अखबार की खबर है। यह बिल कल आना था, मगर लोक सभा से नहीं आया। कल के अखबार की यह दिल्ली की खबर है कि पुलिस ने 250 बच्चों को इसी दिल्ली से पकड़कर दिल्ली के बाहर ले जाकर कहीं छोड़ दिया और इस सर्दी में बड़े आराम से हम एअरकंडीशंड सदन में बैठे हैं और बड़े-बड़े भाषण कर रहे हैं। बिल पास कर रहे हैं, लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं। मगर इसी दिल्ली के अन्दर पुलिस ने 250 बच्चों को सर्दी में ले जाकर बाहर छोड़ दिया ...(व्यवधान)...

श्री उप सभापति: आप खामोश रहिए, उनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... आप खामोश रहिए।

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: आपको क्या तकलीफ है? आपको बच्चों के बारे में हमदर्दी नहीं है! क्या आप यह चाहती हैं कि मैं जो 250 बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, वह बात नहीं की जाए? आपके बच्चे नहीं होंगे, यह अलग बात है। मेरे तो बच्चे हैं, इसलिए मुझे बच्चों की फिक्र है। 250 children ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: उनका कहना है कि अखबार न दिखाएँ। ...(व्यवधान)...

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: सारे लोग अखबार दिखाते हैं। ...(व्यवधान)... इस हाऊस में सारे लोग अखबार दिखाते हैं। मैं अखबार का रेफरेंस इसलिए दे रहीं हूँ कि क्या आपने कभी 250 बच्चों के बारे में सोचा कि उनको किस तरह से पुलिस ने उठाकर यहाँ से 50-60 मील दूर इस सर्दी में छोड़ दिया? जहाँ न तो उनको कोई शैल्टर था, न तो उनके खाना-पानी की कोई व्यवस्था थी। किसी एन० जी० ओ० ने उनको वापस लाकर उन्हें शैल्टर दिया और ढक दिया।

मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूँ कि यह जो आपने 2003 के चार्टर के बारे में जिक्र किया, वह चार्टर कम्प्रिहेंसिव था। चार्टर के अन्दर बहुत-सी ऐसी बातें थीं, जिनके ऊपर हमारा कंसर्न है।

मगर यह जो आपका लेजिस्लेशन आया है, इस लेजिस्लेशन में कोई भी दाँत नहीं है, टीथ नहीं है। मुझे याद है, अहलुवालिया जी इस वक्त यहाँ नहीं हैं। लास्ट वीक, दो-तीन दिन पहले किसी बात पर शायद गुस्से में या प्यार में या मोहब्बत में या फ्रस्टेशन में उन्होंने किसी से कहा था कि क्या तुमने दाँत गिरवी रख दिए? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने भी अपने दाँत गिरवी रख दिए कि यह कमीशन लेकर आए हैं जिसके अन्दर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि कुछ लोगों को माफियाँ मिल जाएँ, वह अलग बात है? हद यह है कि आपकी एच॰ आर॰ डी॰ मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके रिकमेन्डेशन्स के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है उसके जो रिकमेन्डेशन्स आए हैं, उनको भी आपने नहीं लागू किया। क्लॉज पर बोलते हुए मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से उस रिकमेंडेशन को आपने रिजैक्ट कर दिया बिना कोई वजह बताए। आपने क्यों उन रिकमेन्डेशन्स को एक्सेप्ट नहीं किया, जो एच॰ आर॰ डी॰ मिनिस्ट्री की कमेटी ने दिए? उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके, एन॰ जी॰ ओज़॰ और गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गनाइजेशंस और जिन लोगों ने इस एरिया में काम किया है, उनसे बात करके जो रिकमेन्डेशन्स किए थे, आपने उनको क्यों रिजैक्ट कर दिया?

मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, एच॰ आइ॰ वी॰ एड के बारे में अगर कोई उल्लंघन होता है, अगर हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री बच्चों के एच॰ आइ॰ वी॰ एड के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं करती, तो क्या आपका कमीशन उस पर कोई ऐतराज़ कर सकता है या कोई एक्शन ले सकता है? अगर बच्चों के एजुकेशन, जो आपके कमीशन के अन्दर ही मेन्शंड है, जो आपके बिल में भी है और जो अभी आपने भाषण किया है, जो हमारी कन्स्टीट्यूशन में है, आर्टिकल 13(3) के अन्दर if the State can make special provision for children. जिसके अन्तर्गत आप यह लेकर आए हैं। Article 21A: The State shall provide free and compulsory education to all the children from the age of 6 and 14 years. Article 24: No child below the age of 14 years shall be employed to work in a factory, in mine or any other hazardous employment. Article 39: The tender age of children is not abused and the citizens are not forced by economic necessity to enter an occasion... इसी तरह के कितने आर्टिकल हैं, जो हमारे कंस्टीट्यूशन में enshrined हैं, जिसके लिए हमें गर्व है कि हमारा कंस्टीट्यूशन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए यह कहता है। मगर आज बच्चों के जो हालात हैं, क्या वे हमारे कंस्टीट्यूशन की धाराओं में मिले है? Are they fulfilling the Constitutional requirement which we have committed 57 years ago, more than half a century ago when we adopted our Constitution? No. Still, there are many children who are un-educated, still there are many children who go hungry without two square meals, still there are many children who have got no facility for health or welfare. फिर मुझे यह बताइए कि आपके इस कमीशन से क्या होगा? इस कमीशन के जरिए आपका उद्देश्य क्या है? हिन्दुस्तान में इतने कमीशन बनें, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी मुल्क़

7.00 P.M.

में इतने कमीशन नहीं बने होंगे, जितने कमीशन हमारे यहाँ बने हैं। उसके साथ=साथ उतने ही हमारे ओमिशन भी हैं, जितने कमीशन हैं उतने ही ओमिशन हैं। हमारा ह्युमन राइट्स कमीशन है, काश कि बिना कमीशन के हमारे लोगों को ह्युमन राइट्स का प्रोटक्शन होता। हमारे यहां वीमेन्स कमीशन है, काश कि महिलाओं के राइट्स की रक्षा बिना कमीशन के हो सकती। हमारे यहां माइनोरिटीज, एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ और बेकवर्ड कमीशन है, काश कि आज बेकवर्ड क्लास का, एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ और माइनोरिटीज के लोगों के हकूक की रक्षा विदाऊट कमीशन हो जाती।

डिप्टी चेयरमैन साहब, अब यह एक और कमीशन आप लेकर आए हैं। हो सकता है कि यह सरकार की कमिटमेंट हो, हो सकता है कि हम सब ने कहा हो कि कमीशन लाओ, मगर वह कमीशन की जो बात चली थी, तो उस कमीशन के अंदर कुछ ऐसी क्लॉजेज होनी चाहिए थीं। You should have had certain protection for children. You should have some rights to take action against those people who do not do what they are supposed to do. अगर हमारे बच्चे जो एजुकेशन फैसिलिटी से दूर हैं, तो क्या आप एच आर डी मिनिस्टर पर, अपने मंत्री पर कोई दावा कर सकता है यह कमीशन? अगर उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो क्या यह कमीशन उनको बुलाकर बात कर सकता है? सिर्फ अगर चंद चीजों के लिए आपने कमीशन बनाया है और आपने साल में एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे दी, तो कितनी ही रिपोर्टें यहां, दस, पन्द्रह रिपोर्ट रोज सबमिट होती है। वीमेन्स कमीशन जब बनाया था, तब यह बात हमने कही थी कि वीमेन्स कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप पार्लियामेंट में डिसकश नहीं करेंगे, तो यह अन्याय होगा। आज तक क्या वीमेन्स कमीशन की किसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई है? आज तक एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ और बेकवर्ड क्लास की जो रिपोर्ट आती हैं, उन पर कभी कोई चर्चा हुई है? कभी कोई चर्चा नहीं होती। एक कमीशन आप बना देते हैं और फिर एक एडीशन, एक ओमिशन उसके अंदर कर देते हैं।

सर, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहां मेंटली चेलेंज्ड, फिजिकली चेलेंज्ड बच्चे हैं, उनके बारे में अगर सरकार कोई प्रोविजन नहीं करती है, तो क्या आपका यह कमीशन उन पर कोई एक्शन ले सकता है? इसमें मेरे पास बहुत मेटेरियल है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि कुछ लोग ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, फोग वेदर है, शाम का वक्त है, सबको घर जाना है, मगर फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहीं हूँ, अगर मैं इस चीज पर बोलते हुए बिल के क्लॉज पर न बोलूं। जम्मू और कश्मीर को आपने इससे बाहर रखा है। मैं समझती हूँ, मुझे मालूम है कि जम्मू और कश्मीर की अपनी एक अलग पोजीशन है, उसको अपना एक अलग मुकाम दिया है, मगर क्या जम्मू और कश्मीर के बच्चों के साथ कोई अन्याय होगा, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या जम्मू और कश्मीर के बच्चे इस भारत का हिस्सा नहीं है, जो आपने उनको इससे बाहर रखा है? मैं समझती हूँ, जम्मू और कश्मीर के इस वक्त यहां कोई रिप्रजेंटेटिव नहीं हैं, मगर मुझे यकीन है कि डा॰ फारुक अब्दुल्ला यहां मौजूद होते, तो वे भी कहते! जम्मू और कश्मीर के गरीब बच्चे, जो आज इस सर्दी के मौसम में अर्थक्वेक की वजह से खुले में पड़े हैं, इतने वर्षों तक

टेररिज्म को उन्होंने सहा है, अगर वे इस कमीशन के दायरे में आते, तो उनको इससे कुछ लाभ मिलता। मुझे नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर की सरकार या वहां के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जी इस बारे में आपसे कोई आपत्ति उठाते। यह बात आप डिसकस कर सकते थे, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे जम्मू-कश्मीर के हकूक का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि इससे वहां के बच्चों के लिए कुछ बेहतरी की जा सकती थी। आपके क्लॉज 4 में 6 मैम्बर की कमेटी को रखा है। आपको एच आर डी मिनिस्टरी ने एक सजेशन दिया था कि इस तरीके से ह्युमन राइट्स की कमेटी का और चेयरमैन का सेलेक्शन होता है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर उसके प्रेसिडेंट होते हैं, होम मिनिस्टर उसके मैम्बर होते हैं, दोनों हाऊसेस के प्रीसाइडिंग आफीसर्स, स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन साहब उसके मैम्बर होते हैं और उसके साथ-साथ लोक सभा और राज्य सभा के लीडर ऑफ द अपोजीशन मैम्बर होते है। अगर इस तरह का जो आपकी HRD की कमेटी ने दिया था, तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपको उसको मानने में क्या तकलीफ थी? क्योंकि अगर एक अच्छी सिलेक्शन कमेटी उन लोगों को ऐप्वाइंट करेगी, तो मुझे यकीन है कि इस कमीशन की एक अहमियत बढ़ जाती, जिस तरह से ह्युमन राइट्स कमीशन की अहमियत है। आपने क्लाज 16(1) में यह कहा है, सब क्लाज़ (1) में यह कहा है कि आप रिपोर्ट भेजेंगे, मगर क्या आपकी रिपोर्ट पर सरकार का अमल करना मैंडेटरी है? क्या सरकार आपकी रिकमेंडेशन्स को मानेगी या सिर्फ आपकी बात सुनकर बिना कोई वजह दिए उसे रिजेक्ट कर देगी? माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हमारे हाऊस के मैम्बर हैं, मैं टेलीविज़न पर उनका इंटरव्यू सुन रहीं थी, उन्होंने यह कहा था कि हमारी रिकमेंडेशंस सिर्फ रिकमेंडेटरी हैं, मेंडेटरी नहीं हैं, सरकार अगर चाहे तो उन्हें माने, चाहे तो न माने। मैं आपसे पूछती हूं कि फिर ऐसा कमीशन बनाने का फायदा ही क्या है, जिसकी रिपोर्ट, जिसके वर्क, जिसकी रिकमेंडेशन, जिसकी स्टडी के ऊपर सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। आरकाइव्स में जाने से तो बेहतर है कि ऐसा कमीशन आप बनाएं ही नहीं और जो खर्चा इस कमीशन पर हो रहा है, वह बच्चों की बेहतरी पर आप खर्च करें।

मैं आपसे एक बात यहां कहता चाहती हूं कि हम बात करते हैं पीस की, गांधी जी के मुल्क में रहते हैं, पूरी दुनिया में हम बात करते हैं पीस की, अहिंसा की, हिंसा के खिलाफ हम बात करते हैं, टेररिज्म के खिलाफ हम बात करते हैं, मगर आप यह बताइए कि कितने बच्चे हैं जो वॉयलैंस की वजह से आज मारे जाते हैं, कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं दुनिया में, जो आर्म्स से मारे गए और उनके भी हाथ में बंदूकें दी गईं, मेरी समझ में यह नहीं आता, मैंने कई बार यह सवाल किया कि जहां हम पीस की बात करते हैं, बड़ी-बड़ी पीस कॉफ्रेंस करते हैं, कल्चर ऑफ पीस की बात करते हैं, हमारे यहां इंडिया में भी कल्चर ऑफ पीस की एक कॉफ्रेंस हुई थी, जहां हम पीस की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि violence starts in the mind of men वहीं हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादा पैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन पर खर्च होते हैं। हमारी सरकार का जो बजट है, उसमें से कितने परसैंट पैसा बच्चों पर खर्च होता है और कितने परसैंट रुपया या धन सामग्री हमारे आर्म्स एंड एम्युनिशन पर खर्च होती है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? दुनिया में यही है कि आर्म्स एंड

एम्युनिशन पर ज्यादा खर्च होता है, बच्चों पर कम होता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि दुनिया में और हमारे भारत में भी कम्प्यूटर की बहुत तरक्की हो गई है, कम्प्यूटर साइंस में बहुत तरक्की हो गई है, अलग-अलग तरह के प्रोग्राम बनाए हैं। ऐसे खिलौने आज दुनिया में बन रहे हैं, ऐसे बच्चों के प्रोग्राम कम्प्यूटर पर बन रहे हैं, जो शुरू से ही बच्चों के दिमाग में नफरत और वार को इन्कलकेट करते हैं। जब हम बचपन से बच्चों को ऐसे खिलौने देंगे, बंदूकें देंगे, टैंक देंगे और कम्प्यूटर के ऐसे प्रोग्राम देंगे कि उसने एक बटन दबाया और कहा कि मैंने दिल्ली पर या लंदन पर बम गिरा दिया और फिर हम बड़ी-बड़ी कांफ्रेंस करके पीस की बात करेंगे, तो क्या यह सही होगा? क्या हम अपनी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति पूरी कर रहे हैं?

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मुझे मालूम है कि मुझे इस बिल को, आपके इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करना है। मेरी हालत, इतना सब कुछ कहने के बाद, In spite of the fact that I feel that I have a lot of apprehensions, I have lot of fears and I have lot of doubts about the implementation or whatever you have said over here or whatever programmes are there for the children, what we have not done in 57 years, that you will be doing in a couple of years, I have my own doubt, लेकिन मेरी हालत उस इंसान की तरह है, जो पानी में डूब रहा है, जिसको एक तिनके का सहारा भी नहीं है। मगर आप यह मत समझिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इस लेजिस्लेशन को तो हम आपकी बात को मान रहे हैं। मुझे यहां पर गालिब का एक शेर नज़र आता है, शायद इसीलिए कहा होगा, पार्लियामेंट में कई बार कहा गया है-

तेरी बात पे जिए हम, तो यह हमने जाना

के खुशी से मर ही जाते, अगर ऐतबार होता

आपकी बात को अगर हमने मान लिया तो यह झूठ समझकर ही माना है, सच समझकर नहीं माना है। मगर हम आपको सच मान लें तो मारे खुशी के हम इधर ही मर जाते। जिस तरह से महिलाओं के बिल के बारे में हजारों बार इस हाउस में लोगों ने बात उठाई, महिलाओं ने उठाई, कुछ अच्छे पुरुषों ने भी उठाई और चेयर से भी उठाई गई, मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि वही हालत हमारे इस देश के बच्चों की होगी। हो सकता है, मैं उम्मीद तो यही करुंगी कि मेरे डाउट्स, मेरी ना-उम्मीदी, मेरे फीयर्स सब गलत साबित हो, और जो आप चाह रही हैं वह सही हो। मगर यह सब कहने के बाद भी मुझे यकीन है कि शायद आप कुछ कर नहीं पाएंगी क्योंकि आपके कमीशन में कोई ताकत नहीं है, कोई जीत नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकती हैं, खाली पार्लियामेंट में हम लोग At the fag end of this Winter Session we make good speeches with only a few dedicated Members sitting over here.

I wish you all the best and support this Bill. Thank you.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Respected Deputy Chairman, Sir, today's subject is very, very important. I also feel that what Najmaji has said, in a way is correct that nobody is interested in atrocities on women or child welfare, because the entire House seems to be vacant. Whatever it is; it is a very important Bill for us. In a very big and vast country like ours, where there is more than 110-crore population, with low-rate of literacy, no proper family planning, so many children are born every minute and so many children die every minute. This is all because of poverty, ignorance and illiteracy. So, that is why, first, we have to think about the health of the children. Health is a very important thing. If you want a healthy baby, first you have to take care of the pregnant women. Only healthy pregnant women can give birth to a healthy child. In our country, women are neglected so much that when they are pregnant, there is malnutrition and that is why the babies born are undernourished. That is the reason why we have to take care of children and mothers.

Secondly, Sir, this is all happening because of the child marriages. See, in rural areas, the girls are married at the age of 13 or 14 years. When they are not fully developed and not fit to give birth to a child, they are forced to give birth to a child and this is how it happens. So, we have to be careful about all these things.

Thirdly, when the child is born, our first duty is to see that immunization is done at the right time. We see so many children suffering from polio and so many other diseases.This is all because of the ignorance of our rural women who do not have that much knowledge in spite of so much of propaganda about polio vaccination or about other things. Our woman are not so particular. That is why babies our country have to suffer.

Fourthly, Sir, when the child is born, then, we have to think about his or her education. I am given only ten minutes. I will try to be very brief.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give some valid and good suggestions as to how the Commission should function.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Yes, Sir. If you are compassionate to give me a little more time, I think, I can speak a little more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Within the timeframe, you have to give suggestions.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: The suggestion is that, as I said just now, the woman folk is completely neglected in our country. Marriages are

made only for the sake of luxury. I don't think that husbands take care of their wives throughout the life. There might be only a few husbands who take care of their wives very well. But they are used as instruments. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Marriages are made in heaven. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, they are used as instruments. There must be very few men who are very particular about...*(Interruptions)*...

PROF. R.B.S. VARMA(Uttar Pradesh): The same is applicable to wives also. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Yes; yes. They are. I congratulate those who are very sincere. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING, SHRI PRIYARANJAN DASMUNSHI: Both, the Opposition and the Ruling parties know that I am very sincere. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: So, those who are sincere, they are sitting here. Sir, I feel so sorry, but very few people are sincere in our country. (*Interruptions*) So, we have to think of child's education. And, in most of rural areas the children are not sent to schools because there are so many problems. The parents are ignorant. They are uneducated. They don't care for the children and children simply roam here and there. This is all because they have to work in the fields and the children roam here and there. That's why there is a large dropout in the schools. And, to remove the dropout, I think, our Government is doing the best by giving them mid-day meal. By starting this scheme, the droupout rate, at least in my State, Karnataka, has gone down. Sir, this scheme was first started in Tamil Nadu. We also used to criticise this. But after that, now when we have started in Karnataka, we really feel that that is the best thing to attract the children to schools. At least, for the sake of food they come to school. So, this is my one of the suggestions that wherever this scheme has not been introduced, the Government should think of it. The Government is spending Rs. 7,000 crores on the *Sarva Shiksha Abhiyan*. We have to utilize that. At some places, there are no buildings, no schools. And where there are buildings, there are no teachers; where there are teachers, there are no children. So, I think, parents should be punished if they do not send their children to the schools. And, that is one of ways to give them education.

Then, Sir, there are so many other things, like, the child labour. Children are not send at there tender age. This is because if a child works, he bring about Rs. 50/- And, this is because of the poverty. Parents don't understand that their children are working in *bidi* factories, bangles factories, in fields and at other such places. Even in the houses of rich people, they employ some children as servants. That is the mistake that we also commit. That should not be done. There should be some punishment for such things. There are children who are working in hotels. There life is completely spoiled. This thing should be completely checked.

There is one more thing that bring depression among children. Nowdays, the number of divorces is increasing. Husband and wife try to stay alone, away from the joint families. Formerly, there used to be joint families, and there some restriction on the daughter-in-law and son. There was some respect for the elders. The children were looked after by the grandparents. But nowadays, the grandparents are not at all wanted. We are constructing more and more old-age homes. We are sending grand parents to the old age homes. And, the husband and wife, who stay away from their parents, after some time start working. And, then, the problem starts and the divorce comes. When the parents are divorced, when they are separated, its impact is on the children. And, such children are sometimes, sent *anaath ashrams* or day care centres. That is why, these things also should be checked.

My next point is this. We see so many beggars on the streets. Beggars train their children to beg. We see so many ladies carrying small babies in their hands. In this cold season, they roam about here and there begging, and giving a little opium to their children. That also should be restricted. We must send those beggars to beggars homes.

There is so much of wasteland in our country. We must set up some industry or start some work for these beggars. Beggary in our country must be stopped. I think, you agree to that.

Then, Sir, the question of drugs is there. Nowadays, the use of drugs has become very common in colleges and wherever there are young children. So, this must be completely stopped. Sometimes, our Ministry says that ऐसा जो काम करते हैं, उन्हें 6 महीने की सजा, 10 वर्ष की सजा should be given, I think, that is not sufficient. We read in the newspapers that a small girl has been raped by an elderly man. Is this a small thing in our country? It is a shameful thing. We must be ashamed of this. For this also, we are not giving them any punishment. Whenever we say that deterrent punishment should be given, we get the reply that we have to bring a law or we have to bring an amendment or we have to do this or that.

Why not have a *kadak shiksha* for these people so that they will remember it for life long. Their hands or legs should be cut off so that those who see these people will feel ashamed and will say, 'Oh, this man has committed such a mistake, that is why, his hands are cut off.' It is there in the Gulf countries. Why cannot we do that here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want the Saudi law here?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: We have to bring it. You told me to suggest something. ...*(Interruptions)*... You told me just now to suggest something. That is why, I am suggesting. Why not have such a law? Why should we put these men in jail for ten years? Yesterday, I said that life outside jail is very difficult. ...*(Interruptions)*... But, life in the jail is very comfortable. I know this because I was a member in the Bangalore Jail. I have seen. ...*(Interruptions)*... I was a committee member. ...*(Interruptions)*... So far, that opportunity has not come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to correct that. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: They are very comfortable there. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to correct it. You were not in jail. Your were a committee member.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Every evening, all the servants prepare special food, chicken, mutton nicely. They are very much with those people, and they are very happy there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your ten minutes are over.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: You told me to suggest; that is why, I am suggesting. Otherwise. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no problem.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: There is another important thing that I want to say. It is about *bhrun hatya*, that is, killing a child in the womb. This is the mistake committed by women. They think nobody would like giving birth to a girl child. That is why, they go to a doctor and have that examination done. Nowadays, the ratio of girls to boys is 933:1000. The girl child is being killed in the womb of the mother. Doctors who are running these clinics and using the technology, should be taken to task, and the doctors licences should be taken away. Even women who are going in for these types of things like abortion, etc., should also be punished. They do not know that giving birth to a girl is really very precious. There is a saying

that son is a son till he gets married and daughter is a daughter till we are buried. So, when we die, only the daughter comes and cries; nobody else will cry on our dead body. As for boys, they will always be keeping an eye on the bank balance of the father. How much money has been kept in the State Bank of India, Delhi? How much money has been there in the Swiss Bank accounts of both, father and mother...*(Interruptions)*... That is ...*(Interruptions)*...

PROF. R.B.S. VARMA: Is it your experience?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: No, I have already declared in the House that I am a BPL lady. So, I think you remember that I am a BPL lady. I don't even know where the Swiss Bank is. I only know that State Bank of India where. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: उनका अपना अनुभव है क्या? अपने बच्चों का अनुभव है तो बता दीजिए।

श्री उपसभापति: महिलाओं को बात करने दीजिए।

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: बहन जी, क्या यह आपका अपना अनुभव है जो आप बता रही हैं?

श्रीमती बिम्बा रायकर: जो कुछ बोलते हैं, वह सबका अनुभव नहीं होता।

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आपके दस मिनट हो गये हैं।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: It is always better to have girl child. That is what we women have to understand this. If a woman commits this mistake, some punishment must be given to that woman, her husband, and also the concerned doctor. That is what I have to suggest.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, since my time is over, I don't to take much liberty from you. Sir, this is the condition of our country and our children. We have to give more importance to our children. Everytime, whenever we go somewhere and see children, we say, in our big lectures, that you are the pillars of our country. You are the future of our country. We just give a lecture. But when the pillars are strengthend, then only, the building will be strong. If these pillars are not good, how can you except that the building will be strong? That is why we have to take care of the children. We have to strengthen the children. We have to educate them and take care of their health. The Government has to be very particular about their education. We should prevent them from taking drugs and all these things. We have to take care of them.

Lastly, as regards the sex atrocities on children, a serious thought should be given to this. That is why, in the last, I want to say only one word. We always say that for a man's success, there is always a woman behind, but behind every ruined woman, there is always a man. Thank you, Sir.

SHRI MATILAL SARKAR (West Bengal): Sir, at the very outset, I must congratulate the hon.Minster for having brought a very important peice of legislation here, that is, the Commission for Protection of Child Rights Bill, 2005. This is a very laudable Bill, I would say, and by bringing forward this bill, the hon. Minister has brought the most helpless sections of our population to the limelight. Now, the whole of India is observing how the children have got a position of prime focus in our deliberations. In our law-making process also, the children have occupied a prime position after the 58 years of Independence. Sir, the commission, I think will fairly keep up the promises that were expressed in the United Nations Organisations Child Right Convention of 1989. Sir, then, what I would like to point out is one of the most important points. In Clause 3, sub-clause 2 of the Bill, it is said that in the Commission, there will be, at least, two women. Sir when the Bill was introduced, there was no quota for women. But while passing the Bill, two seats have been allotted to women. I think, Sir, the hon. Minister has been very miserly in providing adequate quota for women in the Commission. Sir, this is a Commission which deals with the children. So, here, the women who constitute the class of mothers should be given the place of pride. Sir, what does the mother do? The mother is the best nurse for her child; she is the best guide; she is the best friend and she is the source of all his ideology. All that is good for the child for its future is taught by her; the child is totally depedent on mother till a certain age. So, that is why that class of the population, i.e., women should be given, at least, fifty per cent of the positions in the Commission. Sir, it is because I have moved that amendment. I hope, the whole House will join me in getting this amendment passed. The amendment says, that 'in line 30, for the words 'at least two', the words 'at least three' be substituted. For giving positions to women, we should be unreserved, at least, in this Commission. That is my opinion which I am expressing here.

Sir, while moving the Bill, some reasons where stated why this Bill has been brought forward. Some important points have been mentioned here, i.e., that well-being of the children is a universal aspiration. I must say it is not only universal, but it is our national aspiration also.

Sir, what are the curses that the children suffer mostly from? Sir, I would like to highlight some of the points. Our position is not very satisfactory. If we consider our position by the international yardsticks, we do not find our position very satisfactory in respect of infant mortality rate. We are running at a higher rate than many of the developing countries also. It is, I think, more than 60 per thousand at present. We are consuming less calories than we require in order to have the minimum energy in our body. Sir, the calorie intake is very low in some category of persons; it is less than -- less than one thousand kilocalorie- what is should be. Such is the position.

Coming to child marriages, Sir, there is a law in our country. But, we have seen many incidents taking place in different parts of the country. We are aware of the incident that took place in Madhya Pradesh very recently, where an Anganwadi worker was brutally assaulted, because she wanted to save girl from child marriage. Particularly in areas where feudalism still exists in our country, in all such States, we can see these courses still prevailing. No steps have yet been taken in this regard. Some befitting steps need to be taken.

Sir, coming to premature death, as I said, it is a curse for our country. We are taking about universalisation of primary education. We have adopted a law. What does the law say? (*Time-bell)* -- Sir, I need three more minutes to speak.. The responsibility has been vested with the guardians. If a boy or a girl below the age of fourteen years leaves school, the responsibility lies with the parents and not the State. In the case of the child, who is not even a full-grown national, the responsibility should go to the State. Our law does not define it that way. Thus, we are shirking our responsibility of safeguarding the child.

Sir, there are statistics galore on kidnappings, terrorists attacks, etc. If we go through them, we find that the main victims are women and children. The class of population that suffers the most from this menace of kidnappings is children. They are not only kidnapped, but also sent to foreign countries and even sold there. Children top the list in such kidnappings. It is very painful and shameful.

Sir, what are the areas that need to be addressed and what are the ills that children suffer from? One of the areas is, gender-based mentalities. For want of time, I would not like to dwell upon the issue.

Then there are communal violence and casteist practices. I would like to invite the attention of the hon. Minister to article 13. I don't know, why, casteist practice did not find any place. This is a great menace for the

country. Students belonging to different communities cannot even sit together. There are places in our country where this happens. If I say that in my State of Tripura, we are free from all these, it won't suffice; I would like to speak for the whole country. There are States were children belonging to the religious minorities cannot even sit together, cannot drink water from the same tap, or from the same tubewell.

Hence, this Commission should speak strongly against the menace. I am astonished to find that though communal violence and riots have been mentioned, there is no mention about casteist practices. I would request the hon. Minister to lay special emphasis on these points.

Sir, another area of concern is disabilities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude, Mr. Sarkar. You wanted three minutes and I have allowed it to you.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I shall conclude. In article 13, there is no mention about disabilities. The disabled are the worst section among the children. Sir, if we want to admit any physically challenged child in a orphange or any other safe place, what do we do? We find difficulties in procuring a certificate. these poor children can't go to big hospitals. They can't face even the Medical Board. Since they can't procure the certificate, they will not be able to get shelter in all these orphanages. What about their education, travelling facilities, etc. How can he go to school, if he is a physically challenged child? so, these things should find a place in the functions of the Commission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time do you require.

SHRI MATILAL SARKAR: Jus one minuted, Sir. Under article 16 there is no place for children. I suggest that there should be a platform for the children where they can enjoy life; This may be in the shape of an Advisory Council or something like that. Then there should be some platform where they can speak, where they can express their joys and sorrows, where they can play, where they can take part in cultural mandatory for this Commission. It is missing here. I think, the hon. Minister will throw some light on these issues while replying to the debate. With these words, I support the Bill, thank you.

श्री उपसभापति: श्री अबू आसिम आजमी। आज आप बहुत बोले हैं, इसलिए थोड़ा-सा इस पर भी बोल दीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मुझे

मालूम है, मैंने देखा है कि इस बिल को पेश करने के पहले बाल विकास संगठन, बच्चों के फला बहबूद के लिए जितने संगठन थे और जो एनजीओज़ थे, उन सबसे मशविरा लेकर इस बिल को बनाया गया है। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि यह बिल जो बन रहा है बच्चों की फला बहबूद के लिए, बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके फायदे के लिए, लेकिन माइनोरिटी कमीशन है, महिलाओं की फला बहबूद के लिए कमीशन है, ह्युमैन राइट्स के कमीशन हैं, लेकिन ये सारे कमीशंस जो हैं, इनसे पब्लिक को जो फायदा होना चाहिए, वह फायदा बिल्कुल हो नहीं रहा है। इसलिए मैं यूपीए सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपको एक पॉलिटिकल बिल लाना पड़ेगा कि जा भी बिल पास हो रहे हैं, जो भी इस मुल्क का संविधान है, इस मुल्क का जो कंस्टीटयूशन है, वह कंस्टीटयूशन बहुत जबर्दस्त है, इसमें सारी चीजें ली हैं, लेकिन कंस्टीटयूशन का पालन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमको एक बिल लाना पड़ेगा कि कंस्टीटयूशन की मुखालिफत जो लोग करते हैं, जो लोग उसके खिलाफ चलते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कानून लाया जाए कि वे पकड़ में आ जाएं।

दूसरी चीज यह है कि कानून बनता है, लेकिन वह किताबों में रखा जाता है। कानून पर अमल होना चाहिए। इसके बारे में मुझे थोड़ी-सी चीजें बोलनी है। सर, अभी मुम्बई के अंदर जरदोजी काम करने वाले बच्चे, जो ज़री, एम्ब्रोइडरी का काम करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बिहार से, यूपी से वहां जाकर काम करते हैं, उनकी क्या गलती है? उनके घर में खाने को नहीं है, मां-बाप बेचारे भूखों मर रहे हैं, बूढ़ा बाप दवा के लिए तड़प रहे है।, पैसे नहीं मिल रहे हैं, गांव में उसके पास इतनी खेती नहीं है कि उस खेती से वह अपने बाप का इलाज करा सके। छोटे-छोटे बच्चे, जिनके खेलने-कूदने और पढ़ाई के दिन हैं, उन्हें बेचारे मां-बाप उठा कर किसी शहर में भेज देते हैं। अभी जो एक चाइल्ड लेबर का मामला चला है, उन बच्चों की कोई गलती नहीं हैं कि वे नौकरी कर रहे हो, उनको नौकरी करने का कोई शौक भी नहीं है, वे बेचारे कारखानों में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को पकड़ कर जेल में भेजा गया। उन बच्चों को कई-कई दिन लॉक-अप में रखने के बाद मां-बाप के पास वापस अपने स्टेट में भेजा गया। मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन होना चाहिए कि बच्चों के साथ जो यह जुल्म हो रहा है, वह न हो। हां, बच्चों से काम नहीं करवाया जाए, लेकिन उन बच्चों के भूखे मां-बाप को दवा का पैसा, उनके इलाज का, खाने के पैसे का बन्दोबस्त अगर सरकार करती है, सरकार उनको देती है, जो सरकार को पूरा राइट है कि वे बच्चे कहीं भी काम न करें और वे बच्चे स्कूल जाएं। इस चीज के अन्दर इस बात का ख्याल बहुत जरूरी है।

सर मुझे एक और चीज कहनी है। मैं देख रहा हूं कि आज बच्चे जो एडमिशन के लिए अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं तो उनसे प्रिंसिपल कहता है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि कि अपने मां-बाप को लाओ, उनका इन्टरव्यू लेना है। माँ-बाप बेचारे बहुत गरीब हैं। बच्चों को पढ़ाने की उनकी ताकत नहीं है। अब वे कहीं नौकरी करके कुछ पैसे कमा रहे हैं और बच्चों का पढ़ाना चाहते है। स्कूल देखता है कि अगर मां-बाप पढ़े-लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़-लिख लेते है।, तभी बच्चा अंग्रेजी

पढ़ सकता है, नहीं जा उस बच्चे का एडमिशन नहीं दिया जाता रहा है। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है कि बच्चों के एडमिशन में बच्चों के इन्टरव्यू के साथ-साथ उसके मां-बाप को भी इन्टरव्यू के लिए बुलाता है और मां-बाप कितना पढ़ा-लिखा है, उसका सर्टिफिकेट मांगता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अन्दर एक यह प्रोवीजन होना भी बहुत है।

अभी मुम्बई में एक लाख झोंपड़े तोड़ दिए गए। मां-बाप ने जिस घर में रखा था वहां वे रहते थें लेकिन एक लाख लोगों के सर से छत हट गई उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए, उनके पढ़ने की कोई जगह ही नहीं है। जो बच्चों के लिए ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए किस अगर उनका घर तोड़ दिया जाता है जो कमीशन उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करेगा? यह भी होना बहुत जरूरी है।

छोटे-छोटे बच्चे ट्रेनों में सफर करते हैं। महिलाओं के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन है। मैं इस कमीशन से चाहता हूं कि छोटे बच्चों के लिए भी ट्रेन में डिब्बा रिजर्व हों इस कमीशन में अगर कोई ऐसी चीज आए तो उससे एक अच्छा काम हो सकता है।

अभी पिछले दिनों मैं अखबार पढ़ रहा था। उसमें गुजरात का एक किस्सा आया था। एक मां कह रही थी कि "मेरा पति मार दिया गया, मैरा जवान बेटा मार दिया गया, मेरी एक लड़की है, जिसकी उम्र 12-13 साल है। घर में वह और मैं हूं"। ये लोग एक रिलीफ़ कैम्प के अन्दर ठहरे हैं। वे टॉयलेट जाना चाहते हैं। वह महिला कह रही है कि "जिनके लड़के हैं, वे जो अपने ठहरे हैं वे लेकर बाहर कहीं खेत में, कहीं किसी पेड़ की आड़ में जाकर अपनी हाज़त पूरी कर लेते हैं। टॉयलेट चले जाते हैं। लेकिन मेरा लड़का मार दिया गया है मेरे पास मेरी सिर्फ बच्ची है। अगर मैं उस बच्ची को लेकर जाती हूं जो मुझे लगता नहीं कि मेरी बच्ची और मैं जिन्दा रहूंगी। उनके साथ जो हादसा हुए हैं। जिस तरह से रेप हो रहे हैं, उस तरह से मेरी हिम्मत नहीं हैं अगर मैं टॉयलेट में जाऊँ तो वहाँ 25 लोगों की लाईन लगी है। मैं जाऊँ तो कैसे जाऊं"? इस तरह की चीजें इसमें लाई जाएं कि जिन बेचारे लोगों का खानदान मार दिया गया, उनके बच्चों के रिहैबिलिशन के लिए और इस तरह की चीजें न होने पाएं, इसमें प्रोवीजन जरूर आना चाहिए।

इसके संबंध में मेरे पास मंत्री जी के लिए एडवाइस है। सरकार हर काम नहीं कर सकती, सरकार के पासे इतना फंड भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कमीशन बनेगा, बहुत सारी बातें होंगी। अभी बेरोजगारी दूर करने के लिए 365 दिन में 100 दिन का रोजगार कार्यक्रम लाया गया है। इसमें एक दिन का 60 रुपया मिलेगा। क्या होगा उससे? पैसे ही नहीं हैं, लेकिन कुछ जो आ रहा है। इस तरह से अगर ही शहर में इनके डाटा जमा किए जाएं कि कितने बच्चे गरीब हैं, उनको क्या तकलीफें हैं। इसमें एन॰जी॰ओज॰ की मदद ली जाए। बहुत-सारे लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। इस तरह से उन बच्चों के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत से काम हो सकते हैं।

अभी पिछले दिनों में एक किस्सा पढ़ रहा था कि एक मन्दिर के बाहर एक बच्ची को बिठाया गया था। उधर से एक आदमी जा रहा था। वह रुक गया और उसको लगा कि यह बच्ची जो मेरे पूना

में रहने वाले रिश्तेदार की है।वह आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया ओर फिर से उसे देखा उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि यह मेरी बहन की बच्ची यहां कैसे आ सकती है। लेकिन फिर भी वह थोड़ी देर तक खड़ा रहा। जब एक औरत दूर से आई और उसने उसक बच्ची को गोद में उठाया तो उस आदमी को ऐसा लगा कि इस औरत से इस बच्ची को नफरत है, यह इस बच्ची की मां नहीं हो सकती। इसके बाद उसने जल्दी से पूना फोन किया तो मालूम हुआ कि उसको उस रिश्तेदार की बच्ची किडनैप हो गई है। यह बच्ची वही थी, जो उस मन्दिर के बाहर बिठाई गई थी। जब उस औरत की हरकत से उसे ऐसा लगा कि यह बच्ची इसकी बेटी नहीं हो सकती तो उसने उसको पकड़ा। मामला पुलिस में गया तो मालूम हुआ कि यह किडनैप की हुई बच्ची थी। मैं तो कहता हूँ कि कोई किसी की बच्ची को, छोटी बच्ची को किडनैप करता है, तो उसके लिए एक सख्त-से-सख्त कानून बनाये जाए। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं सऊदी अरब में देखता हूं, जेद्दाह में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां हर जुमा के दिन लोगों की लाशें काटकर टांग दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि ह्युमैन राइट का वायलेशन हो रहा है क्या वायलेशन हो रहा है? एक आदमी किसी का मर्डर कर रहा है, तो खून के बदले खून होना चाहिए। अगर गलती से खून हो गया, तो ठीक है, लेकिन आप जान-बूझ कर रोज एक आदमी को मारेंगे और उसके बाद जेल जाएंगे तो आपको जमानत भी मिल जाएगी और आपके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं करेगा। इसलिए आप रोज मर्डर करते रहो और आपके डर के मारे कोई आपके खिलाफ गवाही तो करने वाला है नहीं। इसलिए काईम वहां नहीं हो रहा है?

बच्चियों की बात हो रही थी। मैं कहता हूं कि ...(समय की घंटी)...हुजूरे सल्लाहो अलेह वसल्लम ने 1400 साल पहले ही वह कह दिया था। जब वे आए थे, जो उस जमाने में बच्चियों को जिन्दा गाड़ दिया जाता था। लेकिन वे हुजूहे सल्लाहो अलेह वसल्लम दुनिया में सब के लिए आए। दुनिया में जितने लोग हैं, ऐहतेराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। उनका यह मैसेज़ था लड़कियों के लिए कि ''जो अपनी तीन बच्चियों को इज्ज़त से पाल ले और उनकी शादी कर दे उसको स्वर्ग में, जन्नत में जगह मिलेगी''। यह मैसेज था हमारे प्रोफेट का। मैं यह कहना चाहता हूँ और एक बाप होने के नाते मैं मैडम की बात का बहुत ही समर्थन करता हूं कि लड़कियों से जितना सुख मां-बाप को होता है, उतना लड़कों से नहीं होता है। अफसोस की बात है कि आज दुनिया तो तरक्की कर रही है, मगर इस दुनिया को बनाने वाले की खुदाई में इंटरफीरिएंस हो रहा है, इस तरह तो दुनिया चलने वाली नहीं है। जब दुनिया में तरक्की नहीं थी, तो मर्दों और औरतों का रेशो बराबर चल रहा था। अब तरक्की हो गई, मशीन आ गई, तो जैसा आपका कहना है कि पंजाब में एक जगह एक हजार बच्चों में 300 बच्चियां कम हैं, यह हालत हो रही है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग बच्चियों को दुनिया में आने के पहले मार देते हैं, उनके ऊपर तो सख्त कानून लागू होना चाहिए।

श्री उपसभापति: कनक्ल्यूड कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं खत्म कर रहा हूं, एक दो बातें और कहनी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का जो कानून है, बहुत जोरदार है। आप जाइए अरब कंट्रीज में, किसी की

हैसियत नहीं जा किसी औरत को छेड़ दे, किसी की हैसियत नहीं जो किसी को किडनैप कर ले। किडनैप होती है, तो उसकी सजा में फांसी भी होती है, उसका कत्ल किया जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। मेरे गांव का एक आदमी है। वह बेचारा उत्तर प्रदेश से वहां जाकर फैक्टरी में मैनेजर बन गया। मालिक ने उसे सारा पैसा दे दिया कि यह पैसा संभालो। अरब लोग थे, उन्होंने देखा कि इंडियन आदमी और सारा पैसा संभालता है, तो उसको मार दिया। अब वे जेल में पड़े हैं। उनके लोग पिछले 6 महीने से यहां मुम्बई में बैठे हुए हैं कि भाई, उसके मां-बाप से एक लेटर दिलवा दो।

श्री उपसभापति: कमिशन ने क्या करना है? वह बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं कानून की बात कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: नहीं, कमिशन?

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, यह रिकमंड करना चाहिए कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो जुल्म ज्यादती हो रही है इस तरह से, बच्चियों पर हो रही है। सर, मैं यह कह रहा था कि वे बैठे हैं 6 महीने से, कि एक लेटर दिला दो, दो करोड़ रुपए, तीन करोड़ रुपए देने को भी तैयार हैं, क्योंकि बगैर लेटर के कोई छूटने वाला नहीं है, उसको फांसी होगी। जब तक उसकी मां या उसका बेटा लिखकर नहीं देगा, वह छूट नहीं सकता, भले ही उसे पूरी की पूरी हुकूमत की सपोर्ट है।

श्री उपसभापति: आप कनक्ल्यूड कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, कनक्ल्यूड ही हो रहा है, मैं खत्म ही कर रहा हूं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मैडम, आप जो यह बिल लाई हैं, यह बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। अगर आपने कमिशन बनाया, बच्चों के फलाबूद के लिए दवाएं भेजी, अस्पताल खोलने का किया, लेकिन बीच में जो नेता जी हैं या दूसरे लोग हैं, वे लोग उसमें खा गए, तो क्या होगा? इसलिए पहले करप्शन को भी खत्म होना चाहिए और इसके लिए भी आपको कुछ रिकमंड करना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं, जो आप यह बिल लाए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[شری ابو عاصم اعظمی "اتر پردیش" : سر، میں اس بل کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس بل کو پیش کرنے سے پہلے بال وکاس سنگھٹن، بچوں کی فلاح و بہبودی کے لئے جتنے سنگھٹن تھے اور جو این.جی.اوز. تھے، ان سب سے مشورہ لے کر اس بل کو بنایا

---

† [ ] Transliteration in Urdu Script.

گیا ہے۔ لیکن مجھے صرف ایک ہی بات کا ڈر ہے کہ یہ بل تو بن رہا ہے بچوں کی فلاح و بہبود کے لئے، بچوں کے ری ہیبلیٹیشن کے لئے، ان کے فائدے کے لئے، لیکن مائنارٹی کمیشن ہے، مہیلاؤں کے فلاح و بہبود کے لئے کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کے کمیشن ہیں، لیکن یہ سارے کمیشنس جو ہیں، ان سے پبلک کو جو فائدہ ہونا چاہئے، وہ فائدہ بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے میں یو. پی. اے. سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک پالیٹکل وِل لانا پڑے گا کہ جو بھی بل پاس ہو رہے ہیں، جو بھی اس ملک کا سدھان ہے، اس ملک کا جو کانسٹی ٹیوشن ہے، وہ کانسٹی ٹیوشن بہت زبردست ہے، اس میں ساری چیزیں لی گئی ہیں، لیکن کانسٹی ٹیوشن کا پالن نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو ایک وِل لانا پڑے گا کہ کانسٹی ٹیوشن کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں، ان کے لئے کوئی ایسا قانون لایا جائے کہ وہ پکڑ میں آ جائیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ قانون بنتا ہے، لیکن وہ کتابوں میں رکھا جاتا ہے۔ قانون پر عمل ہونا چاہئے۔ اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی چیزیں بولنی ہیں۔ سر، ابھی ممبئی کے اندر زردوزی کا کام کرنے والے بچے، جو زری، ایمبرائڈری کا کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بہار سے، یو. پی. سے وہاں جا کر کام کرتے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ماں باپ بے چارے بھوکوں مر رہے ہیں، بوڑھا باپ دوا کے لئے تڑپ رہا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہیں، گاؤں میں اس کے پاس اتنی کھیتی نہیں ہے کہ اس کھیتی سے وہ اپنے باپ کا علاج کرا سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جن کے کھیلنے، کودنے اور پڑھائی کے دن ہے، انہیں بے چارے ماں باپ اٹھا کر کسی شہر میں بھیج دیتے ہیں۔ ابھی جو ایک چائلڈ لیبر کا معاملہ چلا ہے، ان بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہیں، ان کو نوکری کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ بے چارے کارخانوں میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ ایسے بچوں کو پکڑ کر جیل میں بھیجا گیا۔ ان بچوں کو کئی کئی دن لاک اپ میں رکھنے کے بعد ماں باپ کے پاس واپس اپنے اسٹیٹ میں بھیجا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی پراودھان، کوئی پرودژن ہونا چاہئے کہ بچوں کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ نہ ہو۔ ہاں، بچوں سے کام نہیں کروایا جائے، لیکن ان بچوں کے بھوکے ماں باپ کو دوا کا پیسہ، ان کے علاج کا، کھانے کے پیسہ کا بندوبست اگر سرکار کرتی ہے، سرکار ان کو دیتی ہے، تو سرکار کو پورا رائٹ ہے

† [ ] Transliteration in Urdu Script.

کہ وہ بچے کہیں بھی کام نہ کریں اور وہ بچے اسکول جائیں۔ اس چیز کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

سر، مجھے ایک اور چیز کہنی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بچے جو ایڈمیشن کے لئے انگریزی اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے پرنسپل کہتا ہے، اسکول کا ایڈمنسٹریشن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو لاؤ، ان کا انٹرویو لینا ہے۔ ماں باپ بے چارے بہت غریب ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کی انکی طاقت نہیں ہے۔ اب وہ کہیں نوکری کر کے کچھ پیسے کمار ہے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اسکول دیکھتا ہے کہ اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، انگریزی پڑھ اور بول لیتے ہیں، تبھی بچہ انگریزی پڑھ سکتا ہے، نہیں تو اس بچے کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی اسکول ایسا کرتا ہے کہ بچوں کے ایڈمیشن میں بچوں کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی انٹرویو کے لئے بلاتا ہے اور ماں باپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس کا سرٹیفکٹ مانگتا ہے، تو اس پر کاروائی ہونی چاہئے۔ اس کے اندر ایک یہ پروویژن بھی ہونا ضروری ہے۔

ابھی ممبئی میں ایک لاکھ جھونپڑے توڑ دئے گئے۔ ماں باپ نے بچوں کو جس گھر میں رکھا تھا وہاں وہ رہتے ہیں۔ لیکن ایک لاکھ لوگوں کے سر سے چھت ہٹ گئی۔ ان کے بچے پڑھائی سے ونچت ہو گئے، ان کے پڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بچوں کے لئے ایسا پروویژن ہونا چاہئے کہ اگر ان کا گھر توڑ دیا جاتا ہے تو کمیشن ان کے بچوں کی پڑھائی کے لئے کیا کرے گا؟ یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔

چھوٹے چھوٹے بچے ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔ مہیلاؤں کے لئے ٹرینوں میں رزرویشن ہے۔ میں اس کمیشن سے چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لئے بھی ٹرین میں ڈبہ رزرو ہو۔ اس کمیشن میں اگر کوئی ایسی چیز آئے تو اس سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس میں گجرات کا ایک قصہ آیا تھا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی'' کہ میرا پتی مار دیا گیا، میرا جوان بیٹا مار دیا گیا، میری ایک لڑکی ہے جسکی عمر ۱۳، ۱۲ سال ہے گھر میں وہ اور میں ہوں''۔ یہ لوگ ایک ریلیف کیمپ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ٹائلیٹ جانا چاہتے ہیں، وہ مہیلا کہہ رہی ہے'' جن کے لڑکے ہیں وہ تو اپنے لڑکوں کو لے کر باہر کہیں کھیت میں، کہیں کسی پیڑ کی آڑ میں جا کر اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، ٹائلٹ چلے جاتے ہیں، لیکن میرا لڑکا مار دیا گیا ہے، میرے پاس صرف میری بچی ہے۔ اگر میں اس بچی کو لے کر جاتی ہوں تو مجھے لگتا نہیں کہ میری بچی اور میں زندہ رہوں گی۔ ان کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں، جس طرح سے ریپ ہو رہے ہیں، اس طرح سے میری ہمت نہیں ہے۔ اگر میں ٹائلٹ میں جاؤں تو وہاں ۲۵ لوگوں کی

لائن لگی ہے میں جاؤں تو کیسے جاؤں"۔ اس طرح کی چیزیں اس میں لائی جائیں کہ جن بے چارے لوگوں کا خاندان مار دیا گیا، ان کے بچوں کے ری ہیبلیٹیشن کے لئے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائیں۔ اس میں پروویژن ضرور آنا چاہئے۔

اس کے سمبندھ میں میرے پاس منتری جی کے لئے ایک ایڈوائس ہے۔ سرکار ہر کام نہیں کر سکتی۔ سرکار کے پاس اتنا فنڈ بھی نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ کمیشن بنے گا، بہت-ساری باتیں ہوں گی۔ ابھی بے روزگاری دور کرنے کے لئے ۳۶۵ دن میں ۱۰۰ دن کا روزگار کا رنگرم لایا گیا ہے۔ اس میں ایک دن کا ۶۰ روپیہ ملے گا۔ کیا ہوگا اس سے؟ پیسے ہی نہیں ہے لیکن کچھ تو آ رہا ہے، اس طرح سے اگر ہر شہر میں ان کے ڈاٹا جمع کئے جائیں کہ کتنے بچے غریب ہیں، ان کو کیا تکلیفیں ہیں۔ اس میں این جی اوز کی مدد لی جائے۔ بہت سارے لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ان بچوں کے لئے ان کے ری ہیبلیٹیشن کے لئے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔

ابھی پچھلے دنوں میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مندر کے باہر ایک بچی کو بٹھایا گیا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی جا رہا تھا وہ رک گیا اور بچی کو دیکھنے لگا، اس کو لگا کہ یہ بچی تو میرے پونا میں رہنے والے رشتہ دار کی ہے۔ وہ آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا اور پھر اسے دیکھا، اسکی ہمت نہیں پڑھ رہی ہے کہ اس کے بہن کی بچی یہاں کیسے آسکتی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ جب ایک عورت دور سے آئی اور اس نے اس بچی کو گود میں اٹھایا تو اس آدمی کو ایسا لگا کہ اس عورت سے اس بچی کو نفرت ہے، یہ اس بچی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے پونا فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اس رشتے دار کی بچی کڈنیپ ہو گئی ہے۔ یہ بچی وہی تھی، جو اس مندر کے باہر بٹھائی گئی تھی۔ جب اس عورت کی حرکت سے اسے ایسا لگا کہ یہ بچی اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی تو اس نے اسے پکڑا۔ معاملہ پولیس میں گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کڈنیپ کی ہوئی بچی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی کسی کی بچی کو، چھوٹی بچی کو کڈنیپ کرتا ہے تو اس کے لئے ایک سخت سے سخت قانون بنایا جائے۔ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، جدہ میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جمعہ کے روز لوگوں کی لاشیں کاٹ کر ٹانگ دی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے۔ کیا وائلیشن ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کسی کا

مرڈر کر رہا ہے، تو خون کے بدلے خون ہونا چاہئے، اگر غلطی سے خون ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جان بوجھ کر روز ایک آدمی کو ماریں گے اور اس کے بعد جیل جائیں گے تو آپ کو ضمانت بھی مل جائے گی اور آپ کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں کرے گا۔ اس لئے آپ روز مرڈر کرتے رہو اور آپ کے ڈر کے مارے کوئی آپ کے خلاف گواہی تو کرنے والا ہے ہیں۔ اس لئے کرائم وہاں نہیں ہو رہا ہے۔

بچیوں کی بات ہو رہی تھی میں کہتا ہوں کہ.....(وقت کی گھنٹی).....حضرت محمدؐ نے چودہ سو سال پہلے ہی وہ کہہ دیا تھا۔ جب وہ آئے تھے تو اس زمانے میں بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ حضرت محمدؐ دنیا میں سب کے لئے آئے۔ دنیا میں جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفےٰ کے بعد۔ ان کا یہ میسیج تھا لڑکیوں کے لئے کہ" جو اپنی تین بچیوں کو عزت سے پال لے اور ان کی شادی کر دے، تو اس کو سورگ میں، جنت میں جگہ ملے گی۔ یہ میسیج تھا ہمارے پروفیٹ کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ ہونے کے ناطے میں میڈم کی بات کا بہت ہی سمرتھن کرتا ہوں کہ لڑکیوں سے جتنا سکھ ماں باپ کو ہوتا ہے، اتنا لڑکوں سے نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا تو ترقی کر رہی ہے، مگر اس دنیا کو بنانے والے کی خدائی میں انٹرفرینس ہو رہا ہے، اس طرح تو دنیا چلنے والی نہیں ہے۔ جب دنیا میں ترقی نہیں تھی، تو مردوں اور عورتوں کا تناسب برابر چل رہا تھا۔ اب ترقی ہو گئی، مشین آ گئی، تو جیسا آپ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ایک جگہ ایک ہزار بچوں میں تین سو بچیاں کم ہیں، یہ حالت ہو رہی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ جو لوگ بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے ہیں، ان کے اوپر تو سخت قانون لاگو ہونا چاہئے۔

شری اُپ سبھاپتی : کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : سر، میں ختم کر دوں گا، ایک دو باتیں اور کہنی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو قانون ہے، بہت زوردار ہے۔ آپ جایئے عرب کنٹریز میں، کسی کی حیثیت نہیں جو کسی عورت کو چھیڑ دے، کسی کی حیثیت نہیں جو کسی کو کڈنیپ کر لے۔ کڈنیپ ہوتی ہے، تو اس کی سزا میں پھانسی بھی ہوتی ہے، اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گھٹنا میں آپ کو بتا دوں۔ میرے گاؤں کا ایک آدمی ہے۔ وہ بے چارہ اتر پردیش سے وہاں جا کر فیکٹری میں منیجر بن گیا۔ مالک نے اسے سارا پیسہ دے دیا کہ یہ پیسہ سنبھالو۔ عرب لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ انڈین آدمی اور سارا پیسہ سنبھالتا ہے، تو اس کو مار دیا۔

اب وہ جیل میں پڑے ہیں۔ ان کے لوگ پچھلے ۶ مہینے سے یہاں ممبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی، اس کے ماں باپ سے ایک لیٹر دلوادو۔

شری اُپ سبھاپتی : کمیشن نے کیا کرنا ہے؟ وہ بولئے۔۔۔۔۔مداخلت۔۔۔۔

شری ابوعاصم اعظمی : سر، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔

شری اُپ سبھاپتی : نہیں، کمیشن؟

شری ابوعاصم اعظمی : سر، یہ ریکمنڈ کرنا چاہئے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس طرح سے، بچیوں پر ہو رہی ہے۔ سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بیٹھے ہیں چھ مہینے سے، کہ ایک لیٹر دلادو، دو کروڑ روپے، تین کروڑ روپے دینے کو بھی تیار ہیں، کیوں کہ بغیر لیٹر کے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے، اس کو پھانسی ہوگی۔ جب تک اس کی ماں یا اس کا بیٹا لکھ کر نہیں دے گا، وہ چھوٹ نہیں سکتا، بھلے ہی اسے پوری کی پوری حکومت کے سپورٹ ہو۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی : سر، کنکلوڈ ہی ہو رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم، آپ جو یہ بل لائی ہیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن سب سے پہلے بھرشٹاچار کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کمیشن بنایا، بچوں کے فلاح و بہبود کے لئے دوائیں بھیجیں، اسپتال کھولنے کا کام کیا، لیکن بیچ میں جو نیتا جی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ اس میں کھا گئے، تو کیا ہوگا؟ اس لئے پہلے کرپشن کو بھی ختم ہونا چاہئے اور اس کے لئے بھی آپ کو کچھ ریکمنڈ کرنا چاہئے۔

انہی باتوں کے ساتھ میں اس بل کا سپورٹ کرتا ہوں، جو آپ یہ بل لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔

''ختم شد''

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, On behalf of the AIADMK Party and on my own behalf, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Bill. At the outset, I wish to express my whole-hearted and willing support for the Bill, along with others who spoke in favour of the Bill.

Sir, today, I find a peculiar co-incidence. After a hectic activity in the House, we are sitting through the night to legislative over this Bill, which signifies that we emanate and throw light to discuss the darker side of children. Before I put forth my analytical view on the Bill, I am reminded of the background under which the Bill was brought. As everyone is aware, the Constitution of India, in its Directive Principles, envisages various rights and protections to children. Apart from this, the U.N. Convention, as early as 1992, also speaks about children's pride. Thirdly, the National Policy which, apart from including various rights, also envisages the importance of children. Fourthly, the public pressure and populist view also have warranted this kind of legislation.

Sir, as the Chairman and the hon. Members know, in line with our Constitution, dating back to 1950, that is, an old as 55 years, the U.N. Convention, as old as 13 years, the National Policy which is four years old and the original Bill which was initiated three back, presently, this Bill has reached the final stage of enactment. What I am trying to say is that it is better late than never. It has, at last, come. The paramount importance and a unique place that children have are obvious. Children are considered to be a privilege, a pride and prestige of a family and a society. Children are considered to be an asset of a nation. In tamil we call a child as an asset as *Makkal selvam* or *makkal peru*. Sir, it would be more appropriate if I quote a couplet of *Thrukkural* which goes as follows in Tamil and which means that it is much sweeter to hear incoherent, raw words of a child than perfect musical notes emanating from a top-class musical instrument. This is what Thirukkural says. Numerous such illustrations can be cited, as has been done by others also. Nehru's birthday is celebrated as Children's Day. Take the case of our present President. He has immense faith in children. He says that they are vital sources and they are important determinants of the socio-economic development of a country. Sir, we have the largest population of children in the world. Forty per cent of our total population is that of children. This goes to show how much importance children have in our society. But if you look at their condition, it is pitiable. It is very disheartening and disappointing to note the pathetic condition of children in India. Millions of families are living below the poverty line. More

8.00 P.M

so, children are also in the grip of poverty and they are suffering from that pain, with the result that they become rag pickers, pick pockets, petty thieves and chain snatchers, etc. The condition of the girl child is much worse. You know pretty well that a girl child is killed in mother's womb itself. Sometimes, even after birth they are killed or thrown away. The other States may not have such a scheme, but Tamil Nadu has got an excellent scheme for such disowned children and that scheme is known as the Cradle Baby Scheme. This kind of a scheme is there in Tamil Nadu. It may not be available in other States. Sir, children are exploited and abused. As a result, there is no guarantee for their food, education, health and nutrition with the result that they are suffering. Sir, there are about 61 million children who are out of school. Thirty million children in Delhi itself are out of school. Only 0.9 per cent of the GDP is spent on public health. There is only one bed for 3000 people. What I am trying to highlight here is the condition of children in India. Crimes against children have increased these days. The total number of incidents of crime against children has increased by 11 per cent. Incidents of rapes of children are increasing by 60 per cent every year. Cases of murder are increasing by 13 per cent every year. Cases of kidnapping and abduction are increasing every year by 13.7 per cent. What I am trying to state again and again is the condition of children. Though children are considered to be an asset of a society, their condition in our society is pitable. Sir, this is the best time, it is high time, though belated, to bring forward such a legislation. I appreciate, at least, it has come at this stage to become a law. Sir, coming to the core area of my presentation...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I thought you were concluding because you were appreciating it.

DR. K. MALAISAMY: The core area of my presentation is analytical assessment of the Bill. Though the Bill looks all right, I very much doubt whether the entire purpose will be served. According to me, it may not be adequate, as it ought to be. It should be much more comprehensive. My reasons are manifold. Number one: Sir, it is a voiceless and disorganised society. The children are voiceless and unorganised. Will there be any representative out of their own sector to represent their case? It cannot be. It is inherently defective; it is an inherent problem. What are we going to do on that?

Coming to the second problem, Sir, I would like to say that most of the problems for children are not the making of the children, but it is the making of the elders. We are here legislating on behalf of the children.

What are we, the elders, who are responsible for this making, going to do? Kindly think over it. How are we going to tackle this?

Sir, coming to the third problem, as I said earlier, they are in the grip of poverty because millions and millions of families in India are below the poverty line. So, how can the children born in a poor family think of their food, health, etc.? Basically, it is the problem of economics. An economic problem cannot be solved by a legislation, by legal means. That is my point.

Sir, now I come to the list of functions of the National Commission. According to me, it is only illustrative. It cannot afford to be exhaustive. There may be umpteen number of areas which have been omitted.

Sir, my next point is this. The focus given in only protection of children's rights. What about promotion, enitlement of children's rights? Why have you omitted all those things?

Then, I come to the representation of women in the National Commission. Sir, the Bill says that there will be one plus six members. The hon. Minister also being from the fair sex, it has not been spelt out in the Bill why the women are not included in that. Most likely, children can be nicely readopted and taken care of more by women rather than by men. In such a situation, should you not feel that the National Commission, at least, have a sizeable of representation, at least, 30 or 40 or 50. I leave it to you. Sir, I will take two or three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already exceeded your time limit ...*(Interruptions)*..

DR. K. MALAISAMY: Sir, coming to the National Commission again, it is said that it will take care of the recommendations, advisory, etc. I mean, the National Commission should fix up the timeframe on complaints and before that the report should come. How the action plan should be there; how the future action would be taken all these things are not clear in the Bill. I mean, the National Commission should be empowered to fix up the timeframe.

Sir, you may appreciate that the National Human Rights Commission has got a liberal provision saying that whatever is not covered that will be covered under 'any other function'. They have given a clause in the National Human Rights Commission. My question is this. Why don't you have a similar provision in your Commission also?

Sir, now I come to a very, very important point. you have said about setting up a Commission at the National level and at the State level. It is well taken. But, what about the Commission at the district level? the Problem is more at the district level. Should you not think of a district-level Commission? You think over whether the National and State-level Commissions will do, or, you can go for something more.

Sir, My final point is this. There are two Commissions, the National and State Commission. Then, there are about inter-sectoral departments. There are as many as eight departments at the Centre as well as in the States. those eight departments should coordinate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaisamy, it is already there: "Such functions that may be considered necessary for promotion of child right..." It is already there in the Bill.

DR. K. MALAISAMY: I see the point, Sir; if that is the case, then it is okay...*(Interruptions)*...My special point on coordination between the State and inter-sectoral departments is, what exactly is the mechanism you are going to have to do an effective coordination and implementation?

Sir, coming to a very important point....*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should conclude now.

DR. K. MALAISAMY: I will conclude in a minute. When I say so, I would abide by it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Another Member from your Party wants to speak and you should leave some time for her too.

DR. K. MALAISAMY: The AIADMK people never disturb the proceedings of the House. We would not talk much also. In such a situation, the Chair must be extra considerate. Whenever we talk, you must give ten more minutes. Then only would we abide by you and feel that the Chair is taking care of us...*(Interruptions)*...

Sir, about courts dealing with children, the regular judicial officers may not suit in this case.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, you have taken double the time allotted to you...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Not only that, Sir, the courts must be children-friendly. It should be like that.

Finally, Sir, there is some silver lining. The infant mortality rate is coming

down, malnutrition is not there much...*(Interruptions)*... Finally, the Bill can be made more effective and it is up to them to do that.

Thank you Sir.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak.

At this stage, the hon. Member started speaking in Telugu.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you speaking in Telugu? You have not given notice for it.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I know that there is no Telugu Interpreter. I wanted to draw your attention to the fact that there is no Telugu Interpreter since long. I request Mr. Deputy Chairman to appoint an Interpreter in Telugu. that is why I started to speak in Telugu. However, I can also speak in English and there is no problem for me in doing that . I just wanted to draw your attention...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, the hon. Member is right in raising her grievance. If there is no Interpreter in Telugu, it is very unfortunate...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine that.

SHRI S.S. AHLUWALIA: We should look into the case of all the recognised languages, as far as interpretation is concerned. Many times, there were directions from the Chair to the Secretariat to see to it that for all recognised languages under the Constitution there should be Interpreters available so that Members could articulate and vent their feelings in their own regional languages. That is the essence.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I congratulate the hon. Minsiter that she has brought forward a very good Bill, namely, the Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005. It is a very important Bill for the Children because children are the future of our country. Sir, there are many problems which the children are facing. The first problem is right to be born. A UNICEF report last year stated that the mortality rate among babies in the country was 93 per 1000. for example, in Delhi out of 869 born every day, 291 die. But most unrotunate victim is girl child. The girl child is killed in the mother's womb. Day to day the ratio between male and female is falling down. This is rampant in developed States like Punjab, Haryana, Rajasthan and other States. it is a very serious problem. The Government should take effective steps with regard to this issue. Sir, then comes the right to education for those who are lucky to be born. The official figures say that 61 million children in the country are out of school. Nearly 16 per cent of the child population is below the age of 14. There

can be no development without education, more particularly to the girl child. Educate a girl and education the nation, educate a girl, and attain happiness. Undoubtedly educating a girl child will contribute to the national good. Sir, I would like the hon. Minister to give direction to the private schools that they must reserve seats for meritorious students and make a good quality education available to all. Primary education must be linked to incentives. The girl child is still disadvantaged. In some States only 29 per cent of village girl up to 14 years go to schools. for example, in Delhi about 30 per cent children are out of schools. The next problem comes the problem of medical care for children. we are with an unfortunate situation. The Government spends only 0.9 per cent of the GDP on public health. Poor parents in rural areas are so unfortunate that 43 per cent of them take loans of sell their meagre belongings to pay for medicines for their children and other members of the family. Special medical care for children is an unknown phenomenon in rural areas. children in the 0.14 years age group constitute, 44.8 per cent of population. A large share of public expenditure, including investment expenditure is required to be allocated for them. Child marriage is still a big problem in rural areas and this can be addressed through counselling and campaign. The Government should address this problem by allocating adequate financial assistance for this purpose. Sir, lack of food security and poor nutritional status affects the physical growth, intelligence, behaviour, and learning abilities of children, especially during the development of the brain the 0.3 years period. An estimated 30 million children under the age of 5 years need day care. There are only 12,470 creches catering to 3,12,000 children. There is no data indicating the extent to which children are affected by HIV/AIDS, although mother-to-child transmission is a serious problem. Mother-to-child transmission rate can be brought down with drugs. The problem of dissemination against HIV positive children accessing public services like hospitals, schools playgrounds and other facilities need to be addressed. Child trafficking is not merely confined to trafficking for commercial sexual exploitation, but can be for organ transplants, begging.entertainment, child labour, domestic work, drug peddling and participation in armed conflicts. A more comprehensive policy on adoption and faster care of children must be formulated. It should be in consonance with the convention on the Right to Child. There are instances of tribals selling their children in few States and cases are pending in courts. The Child Marriage Restraint Act of 1978 needs to be revised and amended. The problem is not so much a continuation of traditional cultural practices but the emergence of new complex causes. There is growing insecurity of girls and increasing violence against them, adolescent pregnancy from sexual ignorance and neglect, increasing dropouts from post primary schooling due to various reasons

and deep neglect of the physical and cultural development of girls with no provision for games, sports, healthy entertainment, and relating problems.

There is a problem with orphanned children. Government should open more Balvadis and child care centres. Sir, regarding child labour, there is a big problem. You will find lakhs of those boys and girls working in hotels, dhabhas, medicine shops, paper boys etc. The existing acts prohibiting the child labour are not only ineffective but also not implemented in true spirits. The bridge schools are a big useful and needs further strengthening. With these observations, I would like to make some suggestions for the consideration of the hon. Minister. Sir, through you, I would like to request the hon. Minister that we need stronger and more forceful legislation for children. There is an urgent need for revision of laws related to children. Children have no voice and cannot form organised groups to seek help. So we plan to help to incorporate special measures like toll-free phones for 24 hours child help lines. The rights of children can be protected only when our approach is sincere and laws are observed in letter and spirit. The problems innocent children face is many, which are not of their making. It is the elders who are responsible for their difficulties and the poor children simply inherit them. Strict enforcement of relevant legislation along with eradication of the harmful practices of female foeticide/ female infanticide, child marriage, child abuse, child labour, child prostitution etc. should be there. These children should be identified and should be brought to the schools, where residential facility is provided. The major industries and other voluntary organisations should be involved for this noble cause. I am also of the opinion that even exemption can be given to those industries, who contribute to this noble cause. Sir, earlier I made a Special Mention in this august House for the constitution of a separate Ministry or separate department for the children. There are about 26 crores of children in our country and more than four crores of children are working in different fields in the age group of 5 to 14 years. There are many street children apart from orphans. These children are crying for help and the Central Government and various State Governments are not in a position to improve their condition. There are several schemes and programmes which are being implemented by different Ministries and Departments to improve the conditions of children in the country. These include Integrated Child Development Services (ICDS), Nutrition Component of Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY), Balika Samriddhi Yojana, Reproduction and Child Health Programme, National Nutritional Anaemia Control Programme, National Prophylaxis Programme against Blindness due to Vitamin A, Pulse Polio, Universal Immunization Programme, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Programme, Creches and Day Care Centres, Integrated

Scheme for Street Children, Integrated Scheme for Juvenile Justice, Scheme for Elimination of Child Labour, Valmiki Ambedkar Awas Yojana, Swajaladhara, total Sanitation Campaign, etc. In spite of many such programmes, which involve various Ministries, we are unable to achieve the desired results, as there is lack of coordination and cooperation in thse Ministries. Hence, in order to have a comprehensive programme for the all-round development of children and better coordination, we need to have a separate Department or Ministry for Children. Hence, I request the Government of India to create a separate Department for Children, who are the future of our nation. With these words, I welcome the proposal of the Government for establishing the Commission for Protection of Child Rights in this House. I am in total agreement with the laudable objectives of the bill, but, at the same time, I have certain reservations pertaining to certain provisions of the Bill on which I would like to seek certain clarifications. Sir, at the outset, I would like to mention that the word "child' has not been defined in the Bill. Sir, who will be treated as child under this Bill I would like to know from the Minister whether it is importing the definition in some other statute for the purposes of this Bill. further under Clause 3 of the Bill, there is a provision for constitution of the National Commission for Protection of child Rights. It has been provided that the Commission shall have six members and one each from the fields enumerated in the clause. In my view, the scope of the constitution of the Commission should be enlarged and it should have, at least ten Members, with members from other fields, besides those which have been provided for. I would further suggest that half of the Members of the Commission, and particularly the Chairperson, should be women. For example, the Commission is going to involve in various legal activities, therefore, at least, one member from legal faculty having requisite experience must be there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think you have to conclude now.

SHRIMATI VANGA GEETHA : Sir, I will take only three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You should know before hand the time allotted to your party and accordingly you should make your submissions.

SHRIMATI VANGA GEETHA : Sir, my party has got five minutes. You have given me three minutes more. Now, I request you to give me some more time.

Sir, further, the number of years of experience that is required to become a Member of the Commission has not been prescribed. The Members, at

least, should have ten to fifteen years of experience in various fields in order to be eligible for appointment in the Commission.

Under Clause 4 of the Bill, it has been provided that the Chairperson shall be appointed on the recommendation of Three-Member Selection Committee constituted by the Central Government under the Chairmanship of the Minister in charge or the Ministry of Human Resource Development. In order to make the Commission more independent, I propose that the Chairman should be appointed by the President of India on the recommendation of a Committee consisting of the hon. Prme Minister, the hon. Leader of the Opposition from Rajya Sabha and Lok Sabha and the Minister of Human Resource Development. Further, a condition may also be imposed for appointment as a member of the Commission, he/she should not be a retired bureaucrat so that the Commission should not become a channei of partronage for retiring or retired bureaucrats.

Under clause 10 of the Bill, a provision has been made that the Commission shall observe such rules and procedure in the transaction of its business at a meeting as may be prescribed by the Central Government. What is the purpose of giving such a power to the Central Government? Is it not possible to empower the Commission itself to frame and follow its own procedure?

Sir, Clause 15 of the Bill makes the Commission a recommendatory body. It cannot do anything in respect of punishment or imposing any fine. Even the functions, which have been assigned to the Commission, required rewording in order to give more teeth to the Commission. Will the hon. Minister propose to move in the direction making the Commission more powerful?

Now, I come to Clause 17 of the Bill. Sir, it is the most important Clause of the Bill. This Clause empowers the State Governments to constitute State Commissions for protection of child rights. The word used in this Clause is 'may' it is very objectionable. The word'may' gives a wide discration to the States to form or not to form the Commission. There should be an obligation on each State to form the Commission. We have also had the experience of State Commission for Women, where man/States did not care to constitute any Commission in their States. Like the Constitution Seventy-Third Amendment...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have taken more time than that has been given.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I will conclude with this provision. I was Zilla Parishad Chairperson. I came from Panchayat to Parliament in the Seventy-third Amendment also there is a word 'may'. That is why, under the Eleventh Schedule, twenty-nine items have not so far been transferred by the States to Panchayats and local bodies and it is because of the word 'may' I would like the hon. Minister to substitute the word 'may' with the word 'shall'. Therefore, this change should be made. I have also given a notice for amending this.

Further, the number of Members in the State Commission should also be ten, instead of six; and half of them should be women. A provision should also be made in the Bill empowereing the Commission to inquire into the violations of child rights by the Armed Forces and police.

Lastly, Sir, under Clause 25 of the Bill, there is a provision for Children's court. How are these courts going to function along with regular courts and Juvenile courts? There is a wide scope for duplication and overlapping between these parallel judicial bodies. How will they function parallel?

Finally Sir, I would like request the hon. Minister that the Commission should be made more powerful like the National Human Rights Commission. It should be given extensive powers to protect the children's rights and ensure their health growth in an atmosphere which may be conducive to their all round development. Thank you.

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ।

महोदय, आजादी के 58 वर्ष बाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह एवं माननीय मंत्री विदुषी श्रीमती कांति सिंह को बधाई एवं साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इस देश में महिलाओं के लिए कमीशन है, पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन है, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए कमीशन है, अल्पसंख्यकों के लिए कमीशन है, सबके लिए आयोग है, लेकिन इस देश की आबादी के कुल हिस्से का 40 प्रतिशत, जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ था, उस आबादी से सम्बन्धित कोई कमीशन नहीं था। इसलिए आज माननीय मंत्री जी इसे जो इस विधेयक की शक्ल में लाई हैं, इसके लिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ।

महोदय, आज जो देश की स्थिति है, उसमें यह देखा जाता है कि गरीबी और सामाजिक कुप्रथाओं के कारण और सामाजिक मूल्यों और परम्पराओं की अवहेलना के कारण बच्चों, खास कर निर्धन वर्ग के बच्चों की उपेक्षा एवं शोषण के मामले में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसलिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाना एक बहुत ही अनिवार्य कदम था। महोदय, भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कंवेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार

हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए यह जरूरी था कि वे कंवेंशन में उल्लिखित बाल अधिकार के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएँ।

सरकार राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी आयोग बनाने जा रही है और आयोग में महिलाओं की संख्या दो बताई गई है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, वंगा गीता जी ने आयोग के सदस्यों के लिए 10 की संख्या की अनुशंसा की है। कुछ लागों ने कहा है कि इसमें 50 परसेंट महिलाएँ होनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यदि 6 सदस्य भी आयोग में रहेंगे, तो कम-से-कम 3 महिलाएँ अवश्य होनी चाहिए। यदि यह प्रावधान इसमें शामिल करा सकें, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव होगा।

जहाँ तक आयोग के अध्यक्ष के चयन की बात है, उसका चयन 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किए जाने की बात है। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करें, जिसमें मानव संसाधन मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल हों, तो ज्यादा अच्छा हो।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आयोग के बीच सम्बन्धों का परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। जैसा कि अभी वंगा गीता जी ने महिला आयोंग के सम्बन्ध में कहा कि कुछ राज्य की मर्जी थी, तो उन्होंने बना लिया और जिन राज्यों की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाया और बार-बार दबाव देने के बाद महिला आयोग का गठन हो सका। इस प्रकार राज्य और केन्द्र के बीच में एक अनिवार्य सम्बन्ध होना चाहिए, ताकि यह दबाव के स्तर पर, अनिवार्य कानून के स्तर पर इम्लीमेंट किया जा सके। साथ ही साथ इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में भी, दोनों के बीच की सीमा के बारे में भ्रम और विवाद हो सकता है। इसे भी परिभाषित किया जाना चाहिए।

समाज में बालिकाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या तथा अवैध व्यापार की घटनाएँ आम हैं। बच्चों से भीख मंगवाना, कारखानों, होटलों, ईट-भट्ठों आदि जगहों में काम करवाना, यह छिपा हुआ तथ्य नहीं है। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के साथ-साथ अश्लील साहित्य में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे नशीली दवाओं के एडिक्ट हो रहे हैं। आयोग में नशीली दवाओं के आदी बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं कहा गया है। उसको भी इसमें शामिल करना चाहिएं परिवार में बालिकाओं की उपेक्षा के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन सब तथा भविष्य में भी आने वाले बाल अधिकार के संरक्षण से जुड़े हुए मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए एवं सलाह देने के लिए एक बाल सलाहकार ग्रुप का भी सृजन किया जाना चाहिए।

साथ ही मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि बच्चों के संरक्षण के प्रावधान के तहत जो कूडा बीनने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। हम रोज सुबह उठते हैं और दखते हैं कि सड़कों पर जो कूडे का ढेर होता हे, यह छोटे-छोटे शहरों में ज्यादातर दिखाई देता है, बड़े-बड़े महानगरों में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन छोटे शहरों में दिखाई पड़ता है, हर चौक, चौराहे और गलियों में कूड़े का जो अम्बार होता है, छोटे-छोटे शहरों में जब सूर्योदय भी नहीं होता है, उस समय बहुत सारे छोटे बच्चे

एक गन्दा बोरा लेकर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनमें यह कंपीटिशन होता है कि कौन पहले कूड़े के ढेर पर जाएं इस गन्दे कूड़े के ढेर से वे प्लास्टिक चुन कर अलग करते हैं, शीश चुन कर अलग करते हैं लोहे की चीज़ें अलग करते हैं, उन्हें वे सारा दिन इकट्ठा करते हैं और शाम को उन्हें ले जाकर बेचते हैं। उससे जो पैसा मिलता है, उससे वे अपने भरण पोषण का उपाय करते हैं।

मैं चाहती हूं कि इसमें जो तमाम बातें शामिल की गयी हैं, उन में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को भी शामिल करना चाहिए और मानसिक रूप से अपंग और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए भी खास प्रावधान करना चाहिए। महोदय, अक्सर देखा जाता है कि प्राकृतिक आपदा और सांप्रदायिक हिंसा में भी काफी बच्चे शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वह ''सूनामी'' हो या भूकंप हो या गुजरात जैसी सांप्रदायिक हिंसा हो, उनमें जो बच्चे लावारिस और अनाथ हो जाते हैं, उन के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का मुंह देखा जाता है क्योंकि सरकार के पास अलग से ऐसी कोई प्रधिकृत संस्था नहीं है जो उन तमाम अनाथ बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए सामने आ सके। इसलिए ऐसी सांप्रदायिक हिंसा व प्राकृतिक आपदाओं में अनाथ हुए बच्चों के लिए इस आयोग में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, विधेयक की धारा 14 व 15 में उल्लिखित शक्तियों के अतिरिक्त आयोग को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने के अधिकार के साथ-साथ किसी बच्चे के शारीरिक एंव मानसिक रूप से शोषण के मामले जब सामने आते है। जो उस बच्चे और उस के परिवार को भी अंतरिम राहत देने के लिए भी जो छोटा सा अधिकार है, वह अधिकार तक इस आयोग को नहीं दिया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि धारा 14 व 15 को और ज्यादा विस्तारित करने हुए उसे इस प्रकार के अधिकार भी दिए जाएं ताकि आयोग के सदस्य उचित समझे तो वहां अंतरिम राहत पहुँचा सकें। महोदय, धारा 13 में उल्लिखित शक्तियों के अतिरिक्त न्यायालय की अनुमति से बाल श्रम, बालक दुरुपयोग, उन के प्रति क्रूरता और बाल अधिकार हनन के मामले में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार इस में शामिल किया जाना चाहिए। महोदय, मैं यह खास बात कहना चाहती हूं कि यह आयोग भी अन्य आयोगों की तरह सिर्फ सलाह देने, मशविरा देने की संस्था मात्र बनकर न रह जाए, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ न्यायिक अधिकार भी मिलने ही चाहिए क्योंकि यह बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए अगर आयोग को न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं तो यह ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकेगा। महोदय, बच्चों से संबंधित सभी कार्यक्रमों, अभियानों तथा योजनाओं में दखल देने का भी अधिकार इस आयोग को होना चाहिए क्योंकि चाहे आंगनवाड़ी योजना हो, प्राइमरी स्कूल में मिड-डे-स्कीम हो या पल्स पोलियो अभियान हो हो या एच॰आई॰वी॰ संक्रमित बच्चे हों। ये आयोग के दायरे में आ सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए इसकी गाइडलाइंस में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इस के साथ ही प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में इस का विज्ञापन कर इस आयोग के विषय में लोगों को जानकारी भी देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अभाव है, वहां पर दीवार लेखन के द्वारा और पंचायती स्तर पर हमें पंचायती राज के तमाम जन-प्रतिनिधियों

का इसे में सहयोग लेना होगा उन के माध्यम से हम गांव स्तर तक इस आयोग की जानकारी पहुंचा सकते है। इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस विधेयक में उल्लिखित प्रावधान के लिए मंत्री जी को विशेष साधुवाद देना चाहती हूं जिस के अंतर्गत राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या उन के अधिकारों का अतिक्रमण हो तो उन अपराधों के त्वरित विचारण के लिए प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा। बालक न्यायालय के रूप में अगर अलग से न्यायालय हो जाएगा तो निश्चित रूप से बालक से जुड़े हुए अपराध, व्याप्त भ्रष्टाचार और जो तमाम मामले हैं वे वहां जल्दी निपटाए जा सकेंगे और लाखों, करोड़ों की संख्या में केसेज वहां पेंडिंग नहीं पड़े रहेंगे ताकि किशोरों को शीघ्र न्याय मिल सके।

महोदय, रिमांड होम में रहने वाले बच्चों की हालत बड़ी शोचनीय हैं रिमांड होम में जो लड़कियां या लड़के रहते हैं, उनकी हालत इतनी खराब होती है कि ज्यादातर वे वहां से समय मिलने पर भाग हैं। फिर पकड़कर लाए जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सही अर्थ में वे रिमांड होम सुधार गृह बन सकें इस बारे में भी उपाय करने की विशेष आवश्यकता है ताकि वे वहां से अच्छे नागरिक बनकर निकल सकें।

महोदय, मैं अनाथालय की दशा की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस देश में ऐसे अनेक अनाथालय हैं जहां पर अनाथ हुए बच्चों को शरण मिलती है, लेकिन बार-बार यह सुनने में आता है और अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि उन अनाथालयों से भी बच्चों को विदेशियों के हाथों ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यह बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए उस तरह के अनाथालयों को भी इस कानून के दायरे में लाना होगा। इन स्थितियों से निपटने के लिए इस आयोग को उन सारी शक्तियों को दिया जाएगा जिससे इस बाल संरक्षण आयोग के साथ-साथ बालकों के सर्वांगीण विकास में यह आयोग संबंधित सारे मंत्रालयों में भी हस्तक्षेप कर सकेगा और बच्चों से जुड़े तमाम मंत्रालयों के बजट में बढ़ोतरी करा सकेगा।

AN. HON. MEMBER: Sir, is he the last speaker?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Last, but one.

AN. HON. MEMBER: who is that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Manoj Bhattacharya.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, firstly, I must express my annoyance ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I would welcome more Members to participate, but you should also have some ..(*Interruptions*).. Anyhow, please ...(*Interruptions*)...

SHRI AJAY MAROO (Jharkhand): Sir, from out side, Shri Suresh Bhardwaj is there.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to express my annoyance at the fact that this Bill was distributed in the House at about 5.30 p.m., and it has come up for consideration and passing immediately today. In the one-and-a-half years that I have been here, this is the first time the House is working till 8.30 p.m. or, it might work even longer. Well, if it was an urgent Bill that required immediate attention, I could understand that, but as the preamble of the Bill states, there was a declaration of "Survivial, protection and Development of children in 1990 of the United Nations; then, we had the convention on the Rights of the Child in 1992, and, then, we ourselves prepared the National Charter for Children in 2003. So, practically, now, 2005 is over. So, there were three years that have been spent in possibly preparing the Bill, and, in the last minute, on the last working day for legislative business of this Session, this has been pushed into. Apparently, the drafters of the Bill are not aware of the extremely serious issues that are involved in this Bill. It might look like a children's Bill, but it has far wider implications, as far as the relationship between the family and the State is concerned. This, again, I would say, is, yet another Bill from the UPA Bill factory. There have been so many Bills in the last few days. There was the Seed Act. We had the Food Safety and Standards Bill. We had the Disaster Management Bill. Every Bill starts by saying that it is going to look after a particular subject. This particular Bill says that it is going to look after children's rights. The real content is that it appoints one Board, one Committee, one Commission at the national level. Most of the Bill deals with the conditions of appointment of the Chairman, how many Members should there be, what functions should they have. Now, every Ministry is trying to create a parallel Government which has a network starting from Delhi to the States and right up to the district level, so that, everytime the Minister goes anywhere in the country, there will be somebody to attend on him serve tea and to receive him and to garland him. The only difference in the Bill, Mr. Deputy Chairman, Sir, is that this particular Bill stops at the State. You have a National Commission, and you have a State Commission. Fortunately, we don't have a District Commission, or, we don't hae a Ward Commission. For dealing with the children, having a Commission at the State level is not going to help. Mr. Chairman, Sir, I have some experience in other countries of the kind of rules that are prepared. For example, in Switzerland, if the child attains six years of age, then, the parents are obliged to have one additional

bed-room. It is a part of child's right that he must have an independent room after he attains the age of six. If this kind of a right is established somewhere in the United Nations, and if we want to implement it, what kind of machinery will be required. We will require somebody not only at the district level, but also at the ward level. I will give you another example. In the United States, if a mother goes to work and if the child is not properly handed over to a baby sitter, or to a creche, there is a complaint against the mother and that child-care sister comes to the House and she keeps inspecting the houses all the time. Now, if that kind of a problem is there, I think, stopping it at the State level is very inadequate. We will have to have a machinery which goes right up to the wards. Otherwise, nothing will be implemented.

Sir, the Commission will deal with 'complaints'. It doesn't say, 'complaints by whom?' It doesn't say, 'complaints against whom'. For example, if a neighbour makes a complaint, — and it has happened in a number of countries — that the child in his neighbourhood is not being taken proper care of, do you consider that as a proper complaint? Would you accept complaints, for example, against the mother or the father and the parents? This involves a very ticklish issue. For example, if you find a child can't be helped by his parents or by anybody else, you put him in a remand home or in a care centre or whatever it is called. But, in India, the problem is that in most of the centres of that type, the rescue centres or the remand homes, there are ample number of cases of child molestation, both of the male child and the female child. Unless we have a proper system, — they can't be sent to jail — unless we have proper remand homes set-up, which ae clean, which are hygienic and which are well-managed, I do not think this kind of a legislation can have any effect at all. Sir, the Commission has two types of functions. In the first part itself, it says 'that it will study this, it will study the various State laws, it will study international treaties and find out what is required to be done.' That part is okay. But I don't think, we really need a Commission with ten or six members, with half of them women, etc. That kind of Commission, I don't think is really called for. This tendency has started since we accepted the idea of a Regulatory Body every Ministry is trying to have as many regulatory bodies as possible. Look, there has always been the problem of superannuated civil servants and, I must congratulate my friend, hon. Geethaji, that she has clearly recommended that 'no superannuated person should be employed for any of these bodies, with that, I think most of the Ministers will withdraw the Bills that they have already presented, because this is meant to be in terms of 'Yes Prime Minister', a *guango* which is to be offered to those

superannuating civil servants who have obliged the Ministers in some way or the other.

I talked about the kind of the enormous scope of the problem involved. I will also talk of the quality of the work involved, and I don't think, there is any appreciation of the quality of work involved. For example, in Mumbai some people, well-meaning, tried to take away the children from the sex workers arguving that 'staying with the mothers would have an unhygienic, and also a morally-evil effect on those children, and they took a way the children and put in remand homes. All of them started complaining that 'in spite of all, a mother is a mother and that we would like to stay with our mothers and not in any of the remand homes. Sir, the relationship between the parents and the child is a sacrosanct relationship, 'a family is my fote', what they say, and I think what the Government is really trying to do is putting its cotton-picking hands into the family matters. It has absolutely no business to enter into a field where the father, the mother and the child are there, if you say that it will take care of only the orphan children who have nobody to take care of or unless there is a proof that there is a step-mother or a step-father who is deliberately harassing the child, the Commission should have no competence in the matter of resolving the problems of children.

I think, the Bill has been prepared in a hurry. Firstly, it has come from the regular pattern of preparing National Commissions, etc. It is prepared with very little appreciation in the quantum of work involed. It is prepared with very little appreciation in the quality of work and complications of work involved, and it is supposed to create a very highly bureaucratic structure mainly meant for providing *quangos* to the superannuating bureaucrat. I think, it is a very unhealthy development, and I would really like this to be handed over to some kind of a Committee which would examine it in detail.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has already been examined by the Standing Committee. ..(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Let it go to some other Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Manoj Bhattacharya.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you very much, Sir. At last, I got a chance to speak. I am conscious of the time factor. I would not like to test the patience of my friends, who are so serious about

this issue and who are still present in the House! I would just submit to you, with all humility, that it is unfortunate to know about the mood prevailing in the House in spite of this being such a serious piece of legislation? What is the mood of the House? We have so many erudite Members in the House. But, how many of them are present in the House to participate in the discussion, or, even to hear about the rights of the children? I feel very sorry; the numbers may be anything, but it is a very sordid state of affairs. I had thought that after so many years of our independence, when we claim to be members of an age-old civilization, Members would have shown some mercy, at least, for children. Unfortunately, it is not so. That is where lies my doubt, as to how far the Commissions, etc. would be successful.

The proposed legislation is very good. But, I do not know whether this is another type of selectivity and conditionality that is being imposed? Is this sort of Bill only meant to conform to the international requirements, to promote our commercial export interests alone? We know about the many non-tariff barriers existing in the developed countries, where child labour is a clause. Because of the use of child labour, goods are not being accepted by them. This is one of the 'non-tariff barriers'. Nowadays, we are discussing more about WTO. I don not know whether this piece of legislation would be the only remaining clause to be considered there.

This piece of legislation is inextricably linked, as many of my erudite colleagues have said, with so many other issues, so many other socio-economic issues, with our economic policies, social policies, our educational policies and many other policies. My question to the hon. Minister is whether 'childhood' has been defined. Unfortunately, in our country, even after 57 years of Independence, a large number of new-borns do not attain childhood. They die before that. Are you mindful about the neonats? Neonats are babies aged between zero to twenty-eight days.

The child mortality rate is high; it is about 60 per 1000. This is because we are not careful about the neonatal problems. We are absolutely unmindful of them. Most of the Government health institutions do not have any department called the Neonatology Department. So, babies don't attain their childhood. This is a very important area that needs to be taken care of. That is where the question of safe motherhood arises. That is where the question of providing more nutrition to mothers, to the girl child comes.

We talk against privatisation of the health system. That is where our objections lie. Unless we, as a nation, respond to this problem positively,

with all positive intentions, we shall not be able to address this problem. I had the good fortune of knowing some of the foreign countries. There I have seen that they make plans for the child right from its birth. They plan for the child. They construct their cities, their towns, their auditoriums, and plan keeping the children in mind, because they know that once it is planned that way, the children would contribute to a strong nation. Unfortunately, in our country, I must say with all humility, the planners have planned without keeping people in their minds. That is how we have precipitated matters. We have come to a position where we have to go in for a separate legislation, for establishing a Commission, to protect the rights of the children. I find such a situation to be amusing in a civilized society. There should not be any legislations, in fact; the safeguards of children should have been ensured even otherwise. But, unfortunately, we have been unmindful about the planning. That is how we have landed into such a situation where we are trying to conform primarily to UN Resolutions. We are trying to conform to the Resolution that was accepted in 1992 in the United Nations, in 2005, 12 to 13 years after it was accepted internationally.

Sir, I understand the time constraints. Kindly hold your patience for some time...*(interruptions)*...I do understand. It is very sad that this piece of legislation, as my erudite colleague, Shri Sharad Joshi, said in his initial remarks, should have come at some other time. We could have an extensive discussion on this when most of our colleagues could have been present over here. In the parliamentary parlance, perhaps it is the dead of night. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For your information, we are almost adhering to the time allotted for this Bill by the Business Advisory Committee. Though we thought that this Bill will be passing in one hour, but it took the entire time allotted by the Business Advisory Committee. So, there is no question of late or earlier. ...*(Interruptions)*... We have almost taken three hours. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I must say, for advancing the right of children, I can be present here till 12.00, 12.30 or 1.00 o' clock at night. I do not mind it. But what has happened? What I have observed is that every Member had to somehow finish the speech. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The time allotted ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I am not asking for the time allotted. I

am just placing for your consideration that this is my experience that Members have become restless. ...*(Interruptions)*...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Reflection on Members should not go on record. ..*(Interruptions)*..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): It should not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: It is all right. Sir, my whole contention is that we should be very serious about the rights of the children and we should be very careful because this is a social welfare issue. I am giving some suggestions; it is a social welfare issue and we are experiencing that most of the social welfare activities are being privatised or are being given to NGOs. As for example, Sir, you may also kindly remember, when this Education Bill came, the 93rd Amendment came, we asked for zero to fourteen. But it has been made 6 to 14. Now, what will happen to a child from zero to six? They are those children who are nowhere covered. During the time of the NDA Government, I distinctly remember, at the time of 93rd Amendment, I personally moved an amendment and we asked for zero to fourteen. We were from the Left. The State must take the responsibility of zero to fourteen. Unless this is taken care of and unless the Government plays its role in the social activities, we shall not be able to address this problem and, Sir, ..*(Interruptions)*.. It is all right, Sir. I shall not continue my speech when everybody is losing his patience. Thank you.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपनी बात कहने से पूर्व कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, वह सुनाना चाहूंगा।

"यह दौलत भी ले लो, यह शौहरत भी ले लो,

भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन,

वह कागज की किश्ती, वह बारिश का पानी।"

माननीय उपसभापति जी, जिस बचपन के बारे में हम इस आयोग का गठन करने जा रहे हैं उनको वह सावन देखने को नहीं मिलता है। आपको याद होगा इसी सदन में जब हमने चिल्ड्रन चार्टर पर चर्चा की थी तो हमारे सदन के एक प्रमुख सदस्य बालकवि बैरागी जी थे। उन्होंने अपने बचपन की व्यथा सुनाते हुए कहा था कि जब मैं चार वर्ष का हुआ था तो मेरी मां ने सबसे पहला काम किया था कि मुझे एक एल्यूमिनियम का कटोरा पकड़ा दिया था कि जाओ बेटा, अपना पेट

*Expunged as ordered by the Chair.

भरने के लिए और मेरा पेट भरने के लिए भीख मांग करके लाओ। आज जब हम यहां पर चर्चा कर रहे बचपन के बारे में, तब भी हमको वोट की चिन्ता है और हमारा सदन खचाखच भरा रहता है। लेकिन जब हम अपने भविष्य के भाग्य विधाता—कहा जाता है कि Child is the father of man—के बारे में चर्चा करते हैं तो हम बहुत चन्द सदस्य ही यहां पर दिखाई देते हैं।

1990 में यूएनओ की ट्रीटी हुई, 58 वर्ष की आजादी के बाद भी हम अपने देश के बचपन के बारे में सोच नहीं पाये। आज भी वह बचपन या तो कहीं पर झूठी पत्तल चाटता हुआ दिखाई देता है अथवा कहीं ढाबे पर नौकरी करता हुआ दिखाई देता है। हम जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, हमारे घरों में बच्चे ही काम करते हैं, चाहे वह विधायक हों, चाहे संसद सदस्य हों, चाहे बड़े-बड़े उद्योगपति हों, कोई भी हों, उनके घरों में बच्चे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं, हम उनके बारे में कभी विचार नहीं करते। हमने अपने संविधान में एलीमेंट्री ऐजुकेशन कम्पलसरी की है, हमने बहुत से कानून बनाये हैं, लेकिन आज भी उन कानूनों का पालन कोई नहीं करता है और ना ही सरकार की नीयत दिखाई देती है कि उनका पालन करवाया जाये। यहां पर माननीय मंत्री महोदया बैठी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम यूएनओ की 1990 की ट्रीटी के बाद आज उन्होंने एक हिम्मत तो की कि अपना एक टीथलैस और पावरलैस आयोग बनाने के लिए, चर्चा के लिए विधेयक लेकर के आई हैं। यहां महिला आयोग, ह्यमैन राइट्स कमीशन की बात हुई, लेकिन यह आयोग उन आयोगों से भी कम शक्तिशाली है। वहां पर जो चेयरमैन और मेम्बर्स की अपाइंटमेंट का तरीका है, उसको एक हाई पावर कमेटी तय करती है, लेकिन यहां पर मंत्री जी को अधिकार दे दिया गया है कि दो मेम्बर्स सलेक्शन कमेटी वह तय करेंगे और तीन आदमी उस चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे। इसके मेम्बर्स की नियुक्ति कौन करेगा, वही करेगा जिसकी उस समय सरकार होगी। जो उनके हारे हुए प्रत्याशी होंगे, जो उनके साथी होंगे या जिनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात होगी कि इसमें हमको एक रिटायर जज बनाना है या रिटायर ब्यूरोक्रेट को लगाना है या रिटायर्ड किसी पोलिटिशियन को एडजस्ट करना है, तो इस प्रकार की व्यवस्था इस आयोग के लिए जो विधेयक लाया गया है, उसमें की गई है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ह्यमैन रिसोर्सेस मिनिस्टर के स्थान पर जो अपाइंटिंग अथारिटी होगी, जो सलेक्शन कमेटी हो, वह कम से कम हाई पावर्ड हो, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कम से कम हो, दोनों सदनों के अपोजीशन के लीडर्स हों और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लेवल की कमेटी हो, तब इसको कोई अधिकार प्राप्त हो सकेगा अन्यथा इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसमें चेयरमैन की उम्र 65 ईयर्स और मेम्बर्स की उम्र 60 ईयर्स है, मेरी यह समझ में नही आता है कि चेयरमेन तो 65 साल की उम्र तक ठीक-ठाक रह सकता है, अगर वह चेयरमैन बन जाये, अगर चेयरमैन न रहे तो उसकी कार्य करने की शक्ति 60 साल में ही क्षीण हो जायेगी, ऐसा क्यों हुआ है, यह मुझे मालूम नहीं हैं यहां पर शरद जोशी जी ने मांग की है कि इसके लिए कोई कमेटी बना दी जाये, लेकिन यह विधेयक जो यहां पर मंत्रालय द्वारा लाया गया है, यह विधेयक स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमैन रिसोर्सेस डवलपमेंट कमेटी को गया था और कमेटी ने जो रिकमंडेशन्स दी थी, उसकी एक भी रिकमंडेशन को सरकार द्वारा इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। उसकी रिकमंडेशन में कहा गया था कि कम से कम दो विमैन

9.00 P.M.

मेम्बर्स इसमें रखे जायें, चूंकि बचपन के बारे में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे सबसे ज्यादा जानती हैं क्योंकि वे अपने पेट में रखकर 9 महीने तक बच्चे की भूख का इंतजाम करती हैं। लेकिन पार्लियामेंट की उस कमेटी की रिकमंडेशन का प्रावीजन इसमें नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त juvenile courts या स्पेशल कोर्ट हर जिले में या प्रदेश में एक लगाई जाये। लेकिन आज जिस प्रकर से जो juvenile courts के लिए courts बनी हैं या जो बोर्ड बने हैं, क्या वे अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोयटेशन होती है, जो juvenile homes होते हैं, जो वहां पर कोर्ट्स बनाई जाती हैं, उनमें छह-छह महीने तक ट्रायल नहीं होता है, सालों तक बच्चे उनमें रह जाते हैं, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है और संसदीय समिति की रिकमंडेशन के बावजूद इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। इस विधेयक की जो क्लॉज 14 है-उसमें कहीं पर भी ऐसी शक्ति आयोग को नहीं दी गई है कि अगर कहीं पर abuse हो रहा हो चाइल्ड राइट्स का, तो उसके ऊपर वह कोई एक्शन ले सके। वे उसको स्टडी करेंगे, रिव्यु करेंगे, सर्च करेंगे, यही भाषा सारे विधेयक में दे रखी है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट ह्यूमैन रिसोर्सेस मिनिस्टर को सौपेंगे। ह्यूमैन रिसोर्सेज मिनिस्टर कुछ करे या न करे। यह आवश्यक नहीं है। अगर इस प्रकार का ही विधेयक इतनी जल्दी में यहां पर लाया जा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी का समय भी व्यर्थ हो रहा है और इससे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। महोदय, आपने बहुत कम समय दिया है इसलिए मैं आपकी घंटी का ध्यान रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय समिति, जो इस विषय की थी, उसकी एक भी रिकॉमेंडेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। जब 58 साल तक हमने इस विषय पर विचार नहीं किया, जब 1990 में यूएनओ के रेग्यूलेशन के बाद भी हमने 15 साल लगा दिए, इस विधेयक को लाने में, तो आज इतनी जल्दी में इस विधेयक को यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी इस विधेयक को किसी प्रापॅर कमेटी को सौंपकर इसकी रीफ्रेमिंग की जानी चाहिए, इसको शक्तिशाली बनाया जाए क्योंकि हम जानते हैं कि यहां अमेंडमेंट भी देंगे तो वे आज यहां पास नहीं होंगे इसलिए अगर इसको ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह मंत्री जी बताएंगी कि स्टेंडिंग कमेटी के कितने रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज: ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा है कि पूरे रिकॉमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज: इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट कमीशन के बारे में बात की गयी है ग्रांटस के बारे में बात की गयी है उन्होंने कहा है कि पूरे रिकॉमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman of the Standing Committee is also here. Is it your Committee?

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): The Committee discussed this. The hon. Member may be saying about some other Committee. I don't know which Committee he is referring to.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Your Committee's recommendation is not accepted by them.

SHRI SURESH BHARDWAJ: Your Committee's recommendations have not been accepted...*(Interruptions)*.. Nothing has been done.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will reply to that. We would listen to what the Minister is going to say.

श्री सुरेश भारद्वाज: स्टेट कमीशन की बात यहां पर की गयी है। बाकी आयोग जो बने हैं, उसके भी स्टेट कमीशन बनते हैं लेकिन उसके लिए कोई मेनडेटरी प्रोविजन नहीं है कि वहां बनाया ही जाएगा। दूसरी बात, उसकी फंडिंग की बात की गयी है। नेशनल कमीशन को ग्रांट सैंट्रल गवर्नमेंट देगी लेकिन कई जगह बहुत छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, वहां पर कमीशन इस प्रकार के बनते हैं, उसके लिए सरकारों के पास पैसा फंडिंग के लिए नहीं होता है और न ही उनता ज्यादा काम उनके पास स्टेट में होता है, उसकी फंडिंग की व्यवस्था अगर सैंट्रल गवर्नमेंट करे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लाभ होगा और जो काम इसको दिया गया है, चाहे वह काम यथार्तशाली हो या न हो, उसके बावजूद भी जितना भी काम ये करेंगे, उसके लिए अगर सैंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी तो उससे मैं समझता हूं कि अधिक कारगर काम हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह बिल आया है, बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इसको और अधिक ताकत देने की जरूरत है। अगर कमीशन ताकतवार होगा, तभी बच्चों के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं, हमारे देश का जो भविष्य बनने वाला है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं,साढ़े तीन करोड जो बच्चे हिन्दुस्तान में हैं और दुनिया में सबसे अधिक बच्चे हिन्दुस्तान में हैं ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: साढ़े तीन करोड़ नहीं, चालीस करोड़ हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज: जो इस प्रकार के छोटे डाउन ट्रोडन और जो इस प्रकार के पत्तल चाट करके काम करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: छोटे बच्चे ज्यादा है।

SHRI SURESH BHARDWAJ: Largest population in the would चिल्ड्रन की है, उसके बारे में अगर हम भविष्य के लिए विचार करेंगे, देश का भविष्य अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर हम उन्हें देश के अच्छे भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों के बारे में हमें सीरियसली विचार करना चाहिए और इस प्रकार के आयोग अगर बनाए जाएं अगर बनाया जाए तो उनके राइटस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, why don't we make an *ad hoc* comittee of those people who have suggested amendments here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will see to that.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman. Sir, first of all, I must compliment the hon. Minister who has brought forward this Bill here, the Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005. I want to make only two points. On seeing the Bill, in the Financial Memorandum, it has been mentioned that the State Government should take care of and fund the constitution of Children Courts, the Commissioners' salaries, staff and Members' salaries and all the expenses should be incurred by the State Governments. Now, all the State Governments are having their own burden. So, the Central Government should come forward to give special allocation for this Commission and also for the constitution of special court and other things. That is the point I want to make. Also, everybody is speaking about parents, children and everything else. I want to draw the attention to the fact that many parents because of their family situation are dropping their children in the residential schools. It should be taken care of. From the childhood, they are in the residential school. They have been brought up in that schools. But due to the stringent rules and regulations of the school nobody can interfere in the affairs of the school. Neither the Government nor the parents can interfere with their rules and regulations. So many incidents have taken place, and because of the stringent behaviour of the school authorities, so many children are coming out of the school, without the knowledge of the authorities. So, the State Commission should be vigilant about this fact. The Commission should exercise vigilance not only when they receive complaints, but also otherwise. They should exercise vigilance all over the area where children are there because so many incidents are taking place. From the childhood, because of their love and affection, so many incidents take place. All those things should be taken care of. Every hon. Member, who has spoken on this Bill, has suggested that the number of members in that Committee should be large. My suggestion is: Why don;t we have a woman Chairman? One more point. As per the recommendations of the Standing Committee on HRD, the selection of the Chairman Should be done in a manner in which the selection of the Chairman of the National Human Rights Commission is done. This selection should also be done in a non-partisan manner. So, the recommendations of the Department-related Standing Committee on HRD should also be taken into consideration.

Lastly, our hon. leader, Dr. M.G.R. had taken a landmark decision. In 1982, he had initiated the Noon Milk Scheme, and the whole world

appreciated that scheme. Taking cue from that, the present Chief Minister is giving free education, free books, free bicycles, free food, and everything else because she is making students the constructive pillars for this nation. Thank you very much.

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, सभी ने कहा है कि कमीशन बिना दांत का कमीशन है, अगर मंत्री जी उसके लिए denture का प्रबंध कर दें, तो अच्छा होगा।

श्रीमती कांति सिंह: उपसभापति महोदय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005, जो लोक सभा से पास होकर आज राज्य सभा में आया है, इस पर आज यहां विस्तृत चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। सम्माननीय नजमा हेप्तुल्ला जी ने की, श्रीमती बिम्बा रायकर ने की, श्री मतिलाल सरकार, आजमी साहब, मलयसामी जी, वंगा गीता जी, कुमकुम राय जी, शरद जोशी जी, मनोज भट्टाचार्य जी, भारद्वाज जी, एस.जी. इंदिरा जी ...(व्यवधान)....

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): जिन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, वे भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए बैठे हैं।

श्रीमती कांति सिंह: मैं उनके बारे में भी बोलूंगी।...(व्यवधान)... इन्होंने हिस्सा लिया और जिन माननीय सदस्यों ने मौन समर्थन दिया ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: रात के नौ बजे भी इतनी महिलाएं बैठी हैं, महिला मंत्री का हौसला बढ़ाने के लिए।

श्रीमती कांति सिंह: धन्यवाद।

श्री उपसभापति: ये आप सभी का आभार प्रकट करती हैं।

श्रीमती कांति सिंह: सर, सभी माननीय सदस्यों ने आज देश में बच्चों के प्रति जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से हमारे बच्चे एब्यूज हो रहे हैं, इसके प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इस देश के 40 करोड़ बच्चे अभी भी वंचित हैं, उन बच्चों की समस्याओं के प्रति, जो हमारे देश के कल के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, हमारे लिए एसेट के रूप में हैं, उनकी समस्याओं के लिए सरकार के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, बहुत सारे विभाग हैं, जो बच्चों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ ही हमारे ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं, जिनके तहत बच्चों की रक्षा की जाती है। सर, लेकिन इसके बावजूद भी जो समस्याएं बनी हुई हैं, उनके प्रति सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाओं को यहां पर प्रकट करने का काम किया है। उन्हीं भावनाओं की कद्र करते हुए हम लोगों ने यह बाल अधिकार संरक्षण विधेयक, 2005 लाने का काम किया है, ताकि हम उन बच्चों को न्याय दिला सकें।

हमारे बहुत सारे सदस्यों की एक शंका है कि इसमें टीथ नहीं है, इस आयोग को उतनी शक्तियां नहीं दी गई है। मैं बताना चाहूंगी कि जब एनडीए की भी गवर्नमेंट थी, तो इस बिल को लाया गया था, लेकिन उस समय जो सरकार थी, वह समाप्त हो गई, इसके बाद वह वापस हो गया। उस समय के बिल में उतने टीथ नहीं थे, उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी शक्तियां नहीं थीं। लेकिन हम लोगों ने इसमें और भी शक्तियों को देते हुए इस बिल को यहां पर लाने का काम किया है।

जैसा कि सभी जानते हैं कि इस बिल को हम लोगों ने लोक सभा में लाने का काम किया था, उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया और स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशंस की। मैं सभी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहती हूं कि हमारी स्थायी समिति ने जितने रिकमेंडेशंस किए थे, उनमें से हम लोगों ने 9 रिकमेंडेशंस को स्वीकार करने का काम किया हे। जिस तरह से महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं को कम-से-कम 50 परसेंट रखा जाए। मैं यह बताना चाहूंगी कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन बना था, उसमें भी यह प्रावधान रखा गया था कि उसमें 2 महिलाओं को रखा जाए। लेकिन आज यह सब लोग जानते हैं के उसमें 100 प्रतिशत महिलाएं हैं, अध्यक्षा से लेकर सदस्य तक। उसी तरह से इसमें कही कोइ रूकावट नहीं है कि हम महिलाओं को इसमें नहीं रख सकते हैं, बल्कि कम-से-कम दो का प्रावधान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें उन्हें चेयरपरसन नहीं बना सकते हैं या हम और अधिक महिलाओं को मैम्बर के रूप में नहीं रख सकते हैं। इसमें ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, बल्कि इसकी छूट है।

जैसा कि मैं समझती हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद जिस आयोग का गठन होगा, निश्चित तौर पर उसमें हर उन बच्चों को शामिल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्कूल में एड्मिशन नहीं होते हैं, अगर गरीब बच्चे हैं, उनके पास वहां नामांकन के लिए क्वालिटी है, अगर उसे कोई स्कूल नहीं लेता है, तो इसमें भी आयोग दखलअंदाजी कर सकता है, आयोग इसकी जांच कर सकता है।

जहां तक कार्यक्रमों का सवाल है, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम बने हुए हैं, जैसे आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आंगनवाड़ी केन्द्र खोले हैं, इसे पूरे देश में फैलाने का और भी काम किया जा रहा है। इसमें भी पूरे पोषाहार की व्यवस्था है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात है, स्कूल जाने के पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसमें मिड-डे मील स्कीम की भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट का लेबर एक्ट है, जिसके अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे वहां काम करते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था रखी गई है। हमारे बहुत सारे एक्ट बने हैं, जिनके तहत लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। वैसी जगहों पर भी यह आयोग दखलअंदाजी कर सकता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें राज्य आयोग बनाने के लिए प्रावधान लगाना चाहिए कि यह जरूरी हो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में हम इस तरह के दिशा-निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राज्य सरकार की भावना होगी कि वे अपने राज्य के बच्चों को

सही तरीके से प्रोटेशक्न दे सकें, उन का संरक्षण कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी हालत में सेल के बजाय उस में हम लोगों ने यह व्यवस्था रखी है और दिशा-निर्देश यह है कि राज्य आयोग का भी गठन किया जाए।

मेरी बहन ने कहा कि बच्चों की डिफनीशन नहीं दी गयी है, व्याख्या नहीं की गयी है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि यू०एन० कनवेंशन ऑन वाइल्ड राइट्स (सी०आर०सी) में जो दी गयी थी, उस के तहत ही प्रावधान रखा गया है। उस में 18 साल के बच्चों को ही शामिल करने का प्रावधान रखा गया है जोकि राज्य के हर एक्ट में है। सभी लोग जानते हैं कि उस में 18 साल तक के बच्चों का ही प्रावधान रखा गया है। जहां तक बच्चों के पार्टिसिपेशन का सवाल है. ...(व्यवधान)...

SHRIMATI VANGA GEETHA: The definition of 'child' means children between zero and fourteen years.

श्रीमती कांति सिंह: सर, 18 साल का ही है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: It means children below 18 years. It means children between zero and eighteen years.

श्रीमती कांति सिंह: उस में 18 साल के उम्र के बच्चे आ जाएंगे।

सर, आयोग को इतनी शक्तियां दी गयी हैं कि जहां बच्चों के साथ कुकृत्य या दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आयोग उस का *suo motu* भी ले सकता है। उस जगह पर जाकर हस्तक्षेप कर सकता है और आयोग को compensation दिलवाने का भी राइट है। आयोग को हम ने भी टीथ दिए हैं कि अगर बच्चों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है या कोई कार्य सरकार नहीं कर रही है तो आयोग सरकार को सुझाव दे सकता है कि जो नियम हैं और आप के जो कार्य हैं, उन पर इस का इम्प्लीमेंटशन नहीं हो रहा है। वह सरकार को भी सुझाव देगा कि आप को इस तरह से इम्प्लीमेंटशन करना चाहिएं। यहां तक कि जो कार्य बच्चों के हित में नहीं हो रहा है, उस को लेकर आयोग सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के जज को भी कह सकता है कि वहां वह दखलंदाजी करे। इसलिए मैं समझती हूं उसे जितने अधिकार दिए गए हैं, वे किसी से कम नहीं हैं सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को है जिस के तहत हर इंसान उस में शामिल हो सकता है, चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध हो। इस में हम ने सिर्फ बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर प्रावधान रखा है। इस तरह हम ने उसे अधिक-से-अधिक राइट्स दिए हैं।

इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं, वे उन्हें वापिस लेकर इस विधेयक को पास करें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the motion moved by Shrimati Kanti Singh to vote: The question is:

> "That the Bill to provide for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children's Courts for providing speedy trial of offences against or of violation of child rights and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 3, there are three amendments: amendments (Nos. 1 and 2) by Shrimati Vanga Geetha, and amendment (No. 7) by Shri Matilal Sarkar. Are you pressing your amendments?

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I would not like to move the amendments. But I would like to seek an assurance from the hon. Minister regarding the enhancement of women Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has already agreed. She has explained it.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the hon. Minister may give an assurance that she is going to consider all these points. The point is that women should be given priority. It is a field for the women. I am not moving the amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 3 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: now we take up clause 4 of the Bill. There is one amendment (No. 3) by Shrimati Vanga Geeta.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, in view of the assurance given by the hon. Minister, I am not moving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Cluase 4 was added to the Bill.

Cluases 5 to 16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up clause 17. There are three amendments (Nos. 4, 5 and 6) by Shrimati Vanga Geetha.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I want to make a request tc the hon. Minister. I am very much particular about this amendment. What is the problem with the Government to put here a word 'shall? We have experienced it in the case of the Women Commission. So many States have not formed the Women Commission. Similalry, as per the 73rd Amendment, they have not given power to the local bodies becuase of the word 'may'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The feeling of the hon. Member is that if you say 'may', the State Government may not establish the Commission.

श्रीमती कांति सिंह: सर, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Ministry say ...(*Interruptions*)...

श्री रद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आप गुनाह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: पाणि जी, जरा इन पर दया करें।...(व्यवधान)...

श्रीमती कांति सिंह: सर, मैंने कहा कि फेडरल स्टेट्स में हम किसी स्टेट को दिशा-निर्देश नहीं दे सकते हैं कि आप यह करें। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take it up with the State Governments.

श्रीमती कांति सिंह: रूल्स बनाते समय भी यह देखा जाएगा ...(व्यवधान)...रूल्स बनाते समय भी हम देखेंगे।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister about the fate of the Women Commission. Why haven't the States constituted the Women Commission? Sir, in Andhra, we have done so many things for women and children.

डा० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: एश्योरेंस तो दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, while framing the rules, all these things will be taken into considertaion. We shall further negotiate with the State Governments while implementing it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you are not moving them. The question is:

"That clause 17 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clasue 17 was aded to the Bill.

Clauses 18 to 37 were added to the ill.

Cluase 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Titl'e were added to the Bill.

श्रीमती कांति सिंह: सर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को पास किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 A.M. on 23rd December, 2005.

The House then adjourned at twenty-four minutes past nine of the clock till eleven of the clock on Friday, the 23rd December, 2005.

4GIPMRND—285RS—21-07-2006.